ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

चीन की दीवार से भी भारी 5.1 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा

रविवारीय, 17 - 23 अक्टूबर 2021 वर्ष- तीन, अंक -10, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को बधाई

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्यवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा का त्यौहार अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है । उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हम सभी समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराई को खत्म करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने सपरिवार मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर राज्य में अमन- शांति, सुख -समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

राज्य के कुछ जिले अफीम की खेती के लिये कुख्यात हैं, वर्तमान सरकार ने इसे रोकने में गंभीरता दिखायी है तो क्या

रूक पायेगी झारखंड में अफीम की खेती?

वरीय संवाददाता

रांची : झारखंड के सुदूरवर्ती या नक्सल प्रभावित जिलों में अफीम की खेती और उससे होने वाली अकूत आमदनी दशकों से चर्चा में रहा है। चतरा जैसे जिले इसके लिये कुख्यात रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इन जिलों के अंदरूनी इलाकों में अफीम की खेती की जाती है और पुलिस प्रशासन की यहां नहीं चलती। बताया जाता है कि नक्सलियों से लेकर खेती करने वाले सबों को इसमें मोटी आमदनी होती रही है। यही कारण है कि चतरा जैसे जिले के कई लोगों को राजधानी रांची में महंगे जमीन, फ्लैट और चल अचल संपत्ति अर्जित करते देखा गया है।

अब झारखंड सरकार ने इस पर रोक लगाने का प्रयास करना शुरू किया है। झारखंड के नक्सल प्रभावित चतरा जिले में बड़े पैमाने पर हो रही अफीम की खेती रोकने के लिए पुलिस अब ड्रोन की मदद लेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर राज्य पुलिस की ओर तैयार की गयी एक व्यापक कार्य योजना को हरी झंडी दे दी है. यह माना जा रहा है कि चतरा जिले में इस वर्ष लगभग चार हजार एकड़ इलाके में अफीम पोस्त की खेती हुई है. विगत कई वर्षों से पुलिस ने अभियान चलाकर हजारों एकड़ में अफीम की तैयार फसल नष्ट भी की है, लेकिन इसके बावजूद जंगलवर्ती इलाकों में अफीम के धंधे को पूरी तरह रोक पाना मुमकिन नहीं हो पाया है. इस बार राज्य पुलिस ने अफीम की खेती और कारोबार के खिलाफ जो कार्य योजना तैयार की है, उसके पहले चरण में ग्रामीणों को इसकी खेती और कारोबार से दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जिले भर के तमाम पूजा पंडालों में जिला पुलिस-प्रशासन की ओर से पोस्टर लगाकर लोगों को बताया गया कि अफीम की खेती और कारोबार कानूनन जुर्म है. इस जुर्म में पुलिस की ओर से की जानेवाली कठोर कार्रवाई और कानूनन दी जाने वाली सजा के बारे में लोगों को अवगत कराया गया।

वन विभाग ने भी दुर्गा पूजा के मेलों और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के जरिए सरकार की ओर से इस आशय की सूचनाएं प्रसारित की. बताया गया कि अब ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी शुरू की जा रही है और ऐसे में अफीम की अवैध खेती करने वाले लोग पुलिस-प्रशासन की निगाह से नहीं बच पायेंगे. इस जागरूकता अभियान के पोस्टर की लांचिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते एक अक्टूबर को चतरा जिले के इटखोरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की थी।

सांसद, विधायक और पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी इस कार्ययोजना से जोड़ा गया है और हर स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि जिले में किसी भी स्थान पर अफीम की खेती न होने दी जाये।अक्टूबर के पहले हफ्ते में जिले की उपायुक्त अंजलि यादव और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की अगुवाई में जिले भर के पुलिस अफसरों, वन विभाग के अधिकारियों, बीडीओ और सीओ के साथ बैठक कर अफीम की खेती और तस्करी पर अंकुश लगाने के अभियान की कार्ययोजना साझा की थी. इसके बाद जिलों के सभी थानों में स्थानीय प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक की जा रही है।

अफीम पोस्त की खेती के बदले गेंदा फूल और मेडिसिनल प्लांट की खेती से ग्रामीणों को जोड़ने की कोशिश भी इसी कार्ययोजना के तहत शुरू की गयी है. रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की मदद से इस तरह के पौधों की खेती के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर राज्य पुलिस की ओर तैयार की गयी एक व्यापक कार्य योजना को हरी झंडी दे दी है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन की यह पहल कितनी कारगर होती है। क्योंकि अफीम की अवैध खेती से से होने वाली बेतहाशा आमदनी का लालच छुड़वाना एक मुश्किल काम है।

नष्ट की जाती रही है अफीम की खेती

चतरा के बाद झारखंड के कई दूसरे इलाकों में भी अफीम की खेती का ट्रेंड शुरू हुआ तो पुलिस की आंखें खुलीं और वर्ष 2016 से अफीम की फसलों को नष्ट करने का अभियान शुरू हुआ. 2017 में पुलिस ने लगभग डेढ़ हजार एकड़ खेत में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया था.2018 में 1144 एकड़ क्षेत्रफल में लगी फसल नष्ट की गयी थी. पिछले वर्ष भी 710.85 एकड़ और 2020 में भी पुलिस लगभग डेढ़ सौ एकड़ में लगी फसल नष्ट की गयी. इस वर्ष यानी 2021 में जून तक पूरे राज्य 2100 एकड़ इलाके में लगी अफीम की फसल नष्ट की जा चुकी है।

एडवांस में मिलती है रकम

चतरा जिले के कुंदा, प्रतापपुर, लावालौंग, गिद्धौर, कान्हाचट्टी, सिमरिया और इटखोरी में पिछले एक दशक के दौरान अफीम के धंधेबाजों ने अपने नेटवर्क का जबर्दस्त विस्तार किया है. कई इलाकों में ऐसे धंधेबाजों को नक्सलियों का संरक्षण भी मिला. नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां पुलिस की आमदरफ्त कम होती है, वहां देखते-देखते नशे की फसल लहलहाने लगी. इस धंधे में देश के बड़े शहरों से लेकर नेपाल तक के ड्रग्स माफिया ने एंट्री पा ली.

ड्रग्स माफिया ने तो अफीम की खेती करनेवालों को प्रति एकड़ फसल के एवज में चार से पांच लाख रुपये तक देने लगे और इसका नतीजा यह हुआ कि इजी मनी के चक्कर में सैकड़ों लोग इस धंधे से जुड़ गये।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर क्या झारखंड भी कर सकता है? उड़ीसा जैसी पहल

मुरलीधर

झारखंड के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में प्रदूषण कम करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। हाल ही में उड़ीसा भुवनेश्वर में सभी घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने में सफलता के कारण चर्चा में रहा। क्या हम भी इलेक्ट्रिक वाहन निती में उड़ीसा का अनुसरण कर सकते हैं? झारखंड ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को मंजूरी तो दे दी है, पर उस पर ठोस काम कितना हो रहा है?

उड़ीसा सरकार ने सितम्बर के महीने में अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की जिसमें उपभोक्ता एवं इससे जुड़े उद्योगों को कई रियायतें देने की बात कही गयी है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक राज्य के कुल वाहन पंजीकरण का 20 प्रतिशत भाग इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पर्याप्त ढांचे की आज भी भारी कमी है। राज्य सरकार अब इस प्रयास में भी है कि राज्य की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ायी जाए। ऐसे 50 इलेक्ट्रिक बसों के लिए आर्डर पहले ही दिया जा चुका है।

ज्यादतर लोगों ने पिछले कुछ सालों में डीज़ल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को छोड़, ई-रिक्शा अपनाया है। तीर्थ स्थल के तौर पर मशहूर पूरी शहर में ई-रिक्शा का आगमन लगभग चार साल पहले शुरू हुआ और देखते ही देखते यह शहर के आवागमन का एक प्रमुख साधन बन गया। पूरी शहर भारत में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और साल भर यहां बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। ई-रिक्शा के अतिरिक्त, उड़ीसा में कई अन्य इलेक्ट्रिक वाहन भी आम लोगों के बीच जगह बना रहे हैं। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से ओडिशा में 28 सितम्बर तक कुल 95,50,505 वाहनों का पंजीकरण हुआ है। इसमें 7,934 इलेक्ट्रिक वाहन है। यानी राज्य में अभी जितने वाहन हैं उसमें 0.1 प्रतिशत के करीब इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इन इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे अधिक संख्या दो पहिया वाहन की है। इनकी संख्या 6,189 है तो बिजली से चलने वाले तीन पहिया वाहन की संख्या 1,441 है। इसके अतिरिक्त 95 चार पहिया वाहन भी पंजीकृत हैं। उड़ीसा सरकार ने आधुनिक समय से कदम-ताल करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। राज्य के नए लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2025 तक कुल वाहन पंजीकरण का 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। उड़ीसा के नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति में उपभोक्ताओं, निर्माताओं एवं बैटरी का निष्पादन करने वाली कंपनियों के लिए कई तरह की छूट, सब्सिडी तथा अन्य सुविधाओं की घोषणा की गयी है। राज्य सरकार ने बीते 1 सितम्बर को अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की और इस तरह यह देश का दसवां ऐसा राज्य बन गया जिसने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई है और अधिसूचित किया है।

झारखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन को दोगुना करने की तैयारी

संवाददाता

झारखंड में ऐ सौर ऊर्जा प्लांट के लिए जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि चार से पांच एकड़ जमीन से एक मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। एक पठारी राज्य के लिये यह बड़ी चुनौती भी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ ही दिनों वहले कहा है कि खेती की तरह बिजली की भी खेती करें

झारखंड आने वाले कुछ वर्षों में ग्रीन एनर्जी (सोलर एनर्जी) का केंद्र बन सकता है. हालांकि केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए ग्रीन एनर्जी उत्पादन के लिए एक बड़ा टार्गेट तय किया है. अक्षय ऊर्जा दायित्व के जरिये झारखंड को दिये गए 2005 मेगावाट के लक्ष्य के खिलाफ 1995 मेगावाट सौर ऊर्जा से और 10 मेगावाट अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के जरिये ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. जबकि झारखंड सरकार ने अपने ड्राफ्ट पॉलिसी में 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा के जरिये हासिल करने का प्लान बनाया है. सरकार इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने का प्लान बना रही है।

यह भी एक तथ्य है कि 5400 मिलियन यूनिट के अक्षय ऊर्जा दायित्व को पूरा करने में वर्ष 2017-18 तक झारखंड देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे हैं. 2018-19 में झारखंड में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर वाटर हीटर और रुफ टॉप ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयत्रों को आगे बढ़ाने के प्रयास किये गये थे. पर अभी भी राज्य लक्ष्य के काफी पीछे है. क्योंकि 2025 तक राज्य को अपनी ऊर्जा की खपत का 25 फीसदी हरित एनर्जी के जरिये करना है. झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के परियोजना प्रमुख बिजॉय कुमार सिन्हा बताते हैं कि सौर ऊर्जा नीति 2021 को अपनाने के बाद झारखंड पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा. पर झारखंड में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है. क्योंकि एक मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए कम से कम चार से पांच एकड़ जमीन की जरुरत होती है. उन्होंने कहा कि नयी ऊर्जा नीति 2021 को तहत जमीन मालिक प्रोत्साहित होंगे और खेती की विकल्प के तौर पर खेत में सोलर प्लेट लगाएंगे।

हालांकि प्लान बनाने और उसे ठोस रूप में जमीन पर उतारने में राज्य का रिकार्ड बहुत ही खराब रहा है। उसके बावजूद सरकार के प्रोत्साहन, प्लांटलगाने से लेकर बिजली खरीदी का वादा झारखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप बिजली की खेती करें उसे सरकार खरीदेगी

ऊर्जा संकट के बीच सीसीएल ने कोयला उत्पादन और प्रेषण बढ़ाया

संवाददाता

वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम छः माह में कोयले का उत्पादन एवं प्रेषण में 25% की वृद्धि दर्ज की

रांचीः सीसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के पहले छः महीने में उत्पादन एवं उठाव/प्रेषण में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सीसीएल टीम लगातार कोयले का उत्पादन और प्रेषण को और अधिक बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी, सचिव (कोयला), डॉ अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष, कोल इंडिया प्रमोद अग्रवाल और राज्य सरकार का सहयोग मिला है।

कोयले की मांग में अचानक आए तेजी के कारण सीसीएल प्रबंधन पूरे श्रम-शक्ति उपयोग एवं नवीनतम तकनीकी को अपनाते हुए कोयला उत्पादन, प्रेषण, उत्पादकता आदि को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। सीसीएल का पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम छः माह में कोयला उत्पादन 20.26 मिलियन टन (एमटी) था जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह में बढ़कर 25.35 एमटी (25 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया जबकि कोयला प्रेषण में पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह में 26.95 एमटी था जो बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 33.66 एमटी (25 प्रतिशत की वृद्धि) हो गया है यानि वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले छः महीने में उत्पादन एवं उठाव/प्रेषण दोनों में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति बढ़ायी जा रही है ताकि देश में बिजली संकट न हो पाए।

कोल इण्डिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल भी स्वयं लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि सीसीएल ने प्रत्येक शनिवार को 'प्रेषण दिवस' के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। साथ ही पर्यवेक्षकों एवं कोयला कर्मियों के कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कंपनी के निदेशकगण स्वयं कोयला खदानों का दौरा कर रहे हैं ताकि कोयले का उत्पादन एवं प्रेषण बिना किसी बाधा के तेजी से चलता रहे।

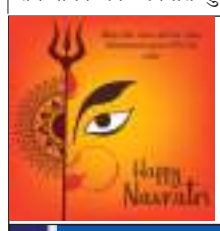

समस्त झारखंडवासियों को शारदीय नवरात्र की असीम शुभकामनायें

आइये अपने झारखंड को संवारें, भुंगरू तकनीक से राज्य को जल संपदा से परिपूर्ण बनायें

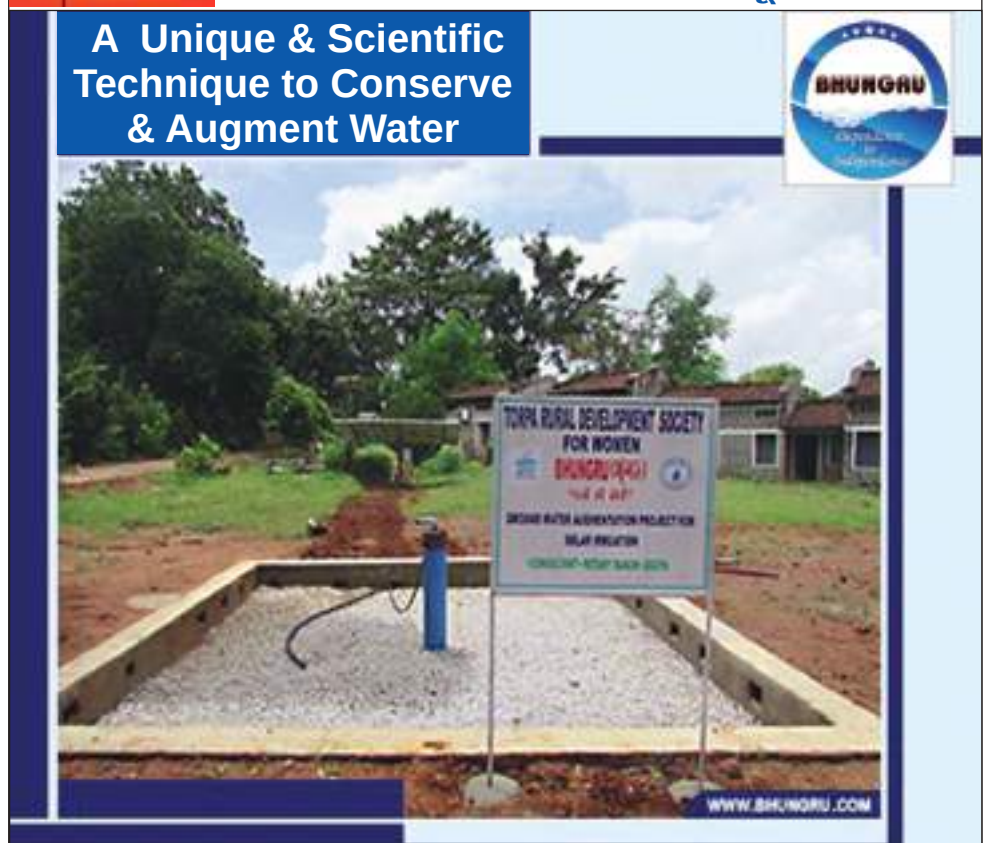

कोविड-19 वैक्सीनेशन में रांची का रिकॉर्ड

संवाददाता

- **मोबाइल वैक्सीनेशन में रांची ने बनाया रिकॉर्ड**
- **1 लाख से ज्यादा लोगों का मोबाइल वैन से किया गया टीकाकरण**
- **28 मई 2021 को 02 मोबाइल वैन से अभियान की हुई थी शुरुआत। अब 11 मोबाइल वैन से हो रहा है टीकाकरण का कार्य**
- **वैक्सीनेशन कवरेज में भी रांची जिला अव्वल**

रांची : कोविड-19 वैक्सीनेशन में रांची में रिकॉर्ड बना दिया है। मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण के कार्य में अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। एक लाख से ज्यादा लोगों को मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण करने वाला रांची राज्य का पहला जिला बन गया है।

रांची जिला में विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत 28 मई 2021 को की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत की थी। 28 मई से 10 अक्टूबर 2021 तक जिला में मोबाइल वैक्सीनेशन के माध्यम से अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया गया है।

रांची जिला में मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत 02 मोबाइल वैन से की गई थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया था। इसके बाद ज़िला प्रसाशन द्वारा 9 और मोबाइल वैन बढ़ाये गए। वर्तमान में कुल 11 मोबाइल वैन के माध्यम से रांची के अलग-अलग जगहों पर लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है।

मोबाइल वैन के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के लिए रांची जिला में कंट्रोल रूम नंबर भी बनाया गया है। 7546028221 पर कॉल कर लोग मोबाइल वैक्सीनेशन के लिए आग्रह कर सकते हैं। एक स्थान पर 50 से ज्यादा लोग होने पर जिला प्रशासन द्वारा उक्त स्थान पर मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण का कार्य कराया जाता है।मोबाइल वैन के माध्यम से रांची जिला में 28 मई 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक अब तक कुल 1804 स्थानों पर टीकाकरण किया गया है।

विदेशी सिगरेट की भारी तस्करी से राजस्व विभाग को हो रहा बड़ा नुकसान

संवाददाता :देश के राजस्व विभाग को एक बड़ा हिस्सा तम्बाखू उत्पादों से प्राप्त होता हैं। लेकिन तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे तस्करी से राजस्व विभाग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। हालांकि समय समय पर इसकी रोकथाम के लिये राजस्व विभाग (उफ्फ्क) द्वारा काफी तादाद में कार्यवाही की जाती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला रुकने का नाम नही ले रहा हैं। तस्करी न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाती है बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी खतरे में डालती है। फिक्की कैस्केड के एक अध्ययन में, यह अनुमान लगाया गया था कि तस्करी के कारण में भारत में (5 उद्योग क्षेत्रों में) 16 लाख से अधिक नौकरियां चली गईं, जिनमें से लगभग 3.34 लाख नौकरी का नुकसान सिर्फ सिगरेट की तस्करी के कारण हुआ था।

गढ़वा में मछली मारने गये चार युवकों की डैम में डूबने से मौत

संवाददाता

मछली मारने के दौरान डैम में डूबने से नाबालिग समेत चार युवकों की मौत हो गयी है. घटना गढ़वा जिला के बंशीधर नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या पांच स्थित बभनी डैम का है. जहां चार पर चार लोग मछली मारने के लिए उतरे थे. जहां वो डैम फाटक के नीचे फंस गये और उनकी मौत हो गयी. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चारों युवक अपने अन्य साथियों के साथ बभनी खाड डैम में मछली मारने गये थे. डैम में उतरने के बाद वो डैम के से निकलने वाले फाटक के माध्यम से बने भव जाल लेकर घुसे थे. फिर जब वो काफी देर तक नहीं निकले तब बाहर मौजूद तीन अन्य साथी डैम के भव के अंदर घुसे और अपने साथियों को आवाज लगायी. पर काफी देर तक आवाज लगाने के बाद तीनों साथियों ने अंदर घुसने का प्रयास किया.

डैम के भव के अंदर जाने बाद तीनों युवकों का भी दम घुटने लगा, इसलिए वो बाहर आ गये. क्योंकि डैम के भव के अंदर दम घुटने वाली स्थिति हो जाती है. इसके बाद मृतकों के साथी बाहर आये और स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी. जानकारी पाने के बाद काफी संख्या में आस-पास के सटे गांव के लोग भी वहां जमा हो गये. घटना की जानकारी मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी और धाना प्रभारी योगेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और डैम का फाटक खुलवाया. फाटक खुलने के बाद डैम के फाटक में फंसे चारों युवको कों नहर के माध्यम से बाहर निकाला गया. चारों युवकों को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।

रांची के ऐतिहासिक रातू किला में विजयादशमी के अवसर पर मां दुर्गा के पूजन अनुष्ठान में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन शामिल हुए । इस अवसर पर राज परिवार की श्रीमती माधुरी मंजरी देवी, नितेश कुमार शाहदेव और उज्जवल नाथ चौधरी ने मुख्यमंत्री का परंपरा अनुसार स्वागत किया ।

सीसीएल के लाल एवं लाडली के रिकार्ड 09 बच्चे चयनित

सीसीएल की लाडली तेजस्वी कुमारी — सीसीएल की लाडली मुस्कान गुप्ता — सीसीएल का लाल बैच टॉपर किशन कुमार

पहली बार सीसीएल की लाडलियों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई कर रचा इतिहास,किशन कुमार 4357 रैंक के साथ टॉपर

संवादाता : सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की महत्वाकांक्षी योजना 'सीसीएल के लाल एवं लाडली' के अंतर्गत इस वर्ष नयी उंचाईयों को छुते हुये बैच के रिकार्ड 09 छात्र जेईई एडवांस क्वालिफाई कर आईआईटी के लिए चयनित हुये। पहली बार सीसीएल की 02 लाडलियों ने जेईई एडवांस क्वालीफाई कर रचा इतिहास। किशन कुमार ने जेईई एडवांस में 4357 रैंक (ओबीसी-751) के साथ अपने बैच में टॉप किया है। किशन कुमार सहित करण राज, आशु कुमार, तेजस्वी कुमारी, अनुज कुमार, मुस्कान गुप्ता, विशाल कुमार, शुभम कुमार, बिट्टू यादव ने सफलता प्राप्त की। कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद प्रत्येक वर्ष की भांति बच्चों ने अपने फैकल्टीज के मार्गदर्शन में शानदार प्रदर्शन जारी रखा। छात्राओं के चयन से न सिर्फ इस योजना का एक नया अध्याय खुला है बल्कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' मुहीम सीसीएल के प्रयास से झारखण्ड राज्य में सशक्त हुई है।

सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद, निदेशकगण एवं विभागाध्यक्ष (सीएसआर) ने जेईई एडवांस क्वालीफाई कर आईआईटी में चयनित होने पर सभी सफल छात्रों को हार्दिक बधाई दी तथा सफल करियर के लिए शुभकामनाएं दी।

सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान-4 द्वारा सफाई कार्यक्रम का आयोजन

रांची :सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर द्वारा स्वच्छता माह के उपलक्ष्य में स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत नागपुर मुख्यालय कार्यालय परिसर में साफ-सफाई (उ'ींल्ल'ल्ली२२ उ्न५ी) कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता की आदत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की एवं स्वच्छता का संदेश दिया । इस कार्य में कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ के भाग लिया। इसके पूर्व नागपुर में ही स्वच्छता माह के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने एवं संस्थान के कर्मचारियों तथा जन सामान्य को कोविड से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए बैकलिट फ्लेक्स संस्थान के मुख्य द्वार पर लगाया गया ।

गिरिडीह में एक हफ्ते में हाथियों ने ली 6 लोगों की जान, कई घरों को किया बर्बाद

संवाददाता

गिरिडीह में गुरुवार को हाथियों के झुंड ने दो लोगों को कुचल कर मार डाला. इससे पहले भी इलाके में हाथियों ने कई जगह उत्पात मचाया है। गिरिडीह में एक हफ्ते में हाथियों ने ली 6 लोगों की जान, कई घरों को किया बर्बाद, इलाके में दहशत फैला रखा है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. हादसा गुरुवार को हुआ. हाथियों के हमले से यहां एक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक को घायल कर दिया. जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. इसी हफ्ते की शुरुआत में एक हाथी ने चार लोगों को मार डाला था।

दरअसल हाथियों का झुंड गुरुवार देर रात अंबाडीह गांव में घुस गया था और उसने एक व्यक्ति को मार दिया था जबकि दूसरे को जख्मी कर दिया था. हाथी के हमले में घायल व्यक्ति की भी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के झुंड ने गांव में झोपड़ियों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.

दुर्गा पूजा पंडाल को भी नहीं बख्शा

बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने वन विभाग से पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है. इस हफ्ते के

शुरू में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने पड़ोसी हजारीबाग जिले में चार लोगों को कुचलकर मार डाला था. यही हाथी 12 अक्टूबर को झारखंड के दारू में दुर्गा पूजा पंडाल में घुस गया था, जिससे भक्तों में दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई थी. भगदड़ में 24 लोग घायल हो गए थे. जंगली हाथियों ने एक महीने पहले बगोदर थाना क्षेत्र में भी जमकर उत्पात मचाया था. हाथियों ने खंभरा, बनपुरा, हेसला आदि गांवों में कई घरों और चाहरदिवारियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था. इस दौरान हाथियों ने घरों में रखे अनाज को चट कर गया था. वहीं खेतों में लगे फसलों को भी रौंद दिया था. जुलाई के अंतिम सप्ताह में हाथियों ने तीन लोगों को कुचला था. इसमें इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी. उक्त घटना भी सरिया थाना क्षेत्र के सखुवाडीह गांव की है।

रेलवे ने तीन कर्मचारियों को पुरस्कृत किया

संवाददाता

रांची : 13अक्टूबर को मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने महीने के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिये 03 कर्मचारियों को इम्पलॉई ऑफ द मंथ योग्यता प्रमाण पत्र एवं नगद राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया एवं 01 कर्मचारी को अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (परिचालन) एम एम पंडित ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया ।

जीतू राम महतो ट्रैक मेंटेनर, किता को अपने ड्यूटि के दौरान किलो मीटर संख्या 367/25-27 के बीच रेल फ्रेक्चर देखा , उन्होने शीघ्र पटरी को नियमानुसार सुरक्षित किया एवं इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी । महतो की सतर्कता ने दुर्घटना को टाल दिया एवं उनके इस कार्य ले लिए मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने मई महीने का एंप्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार एवं नगद राशि से पुरस्कृत किया गया।

हेमलाल लकड़ा, वेलफेयर इंस्पेक्टर ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान वायरस के कारण मृत कर्मचारियों के परिजनो को आर्थिक मदद एवं अन्य भुगतान बहुत ही कम समय में निष्पादित करने का कार्य किया साथ ही रांची रेल मण्डल के कोरोना वायरस से पीडित कर्मचारियों की सूची को निरंतर अपडेट रखा, उनके इस उत्कृष्ट कार्य ले लिए मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप ने जून महीने का एंप्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार एवं नगद राशि से पुरस्कृत किया गया।

जनक साहू पॉइंट्स मैन, गोविंदपुर 26 डिब्बे के एक्सएल बॉक्स के 3 में से 2 नट गिरा देख शीघ्र ट्रेन के गार्ड को लाल सिग्नल दिखाया और इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। यांत्रिक विभाग के मरम्मत करने के बाद गाड़ी को रवाना किया गया उनके इस सजगता के लिए प्रदीप गुप्ता द्वारा जुलाई महीने का एंप्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार एवं नगद राशि से पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री को छतीसगढ से निमंत्रण

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र के माध्यम से आगामी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित "राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021" में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया है। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से विधायक एवं संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन विनोद चंद्राकर ने मुलाकात की तथा उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रण पत्र दिया।

विनोद चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में देश और विश्व की सबसे प्राचीन आदिम सभ्यताएं आज भी जीवित हैं। इन सभ्यताओं के संरक्षण तथा उनके मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी का सीसीएल दौरा

संवाददाता : कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सीसीएल एवं बीसीसीएल के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की 14 अक्टूबर को सीसीएल, मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में कोयला, खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सीसीएल के कार्य निष्पादन की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विशेषकर पावर प्लांटों को कोयला आपूर्ति, कोयला उत्पादन सहित अन्य मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पी.एम. प्रसाद ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कंपनी के कार्यनिष्पादन, योजनाओं, उपलब्धियों एवं चुनौतियों के बारे में मंत्री महोदय को विस्तार से जानकारी दी। समीक्षा बैठक में प्रल्हाद जोशी ने कोयला उत्पादन के साथ-साथ पावर प्लांटों में आपूर्ति संबंधी सीधी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के उपरांत देश एक बार पुनः आर्थिक विकास की राह पर दौड़ रहा है। देश की मुख्य ऊर्जा संस्थान होने के कारण इस रफ्तार को कायम रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं कोयला मंत्रालय आपको सभी प्रकार के सहयोग एवं सहायता के लिए तत्पर है। प्रल्हाद जोशी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कोयला खनन में आने वाली आधारभूत समस्याओं को दूर करने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया।

इस बैठक में अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार विनोद कुमार तिवारी, अध्यक्ष कोल इंडिया, प्रमोद अग्रवाल, सयुंक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, बी पी पति, सीसीएल एवं बीसीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद; सीएमडी ईसीएल, पी एस मिश्रा, सीएमडी, सीएमपीडीआई, मनोज कुमार, निदेशक तकनीकी (संचालन), सीसीएल, वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकीनीकी (योजना/परियोजना), सीसीएल, भोला सिंह, निदेशक (कार्मिक), सीसीएल, पी.वी.के.आर. मलिकार्जुन राव, माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव, होन्नारेड्डी एन, ईडी, कोल इंडिया, श्री एम के सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

पिपरवार क्षेत्र का दौरा किया

प्रल्हाद जोशी ने पिपरवार क्षेत्र के अशोका ओपनकास्ट खदान एवं बचरा रेलवे साइडिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने कोयला उत्पादन में लगे कर्मियों का उत्साहवर्धन किया ।अभी देशभर के पावर प्लांटों में कोयले की कमी की खबर के बीच कोयला मंत्री का यह दौरा अंत्यत महत्वपूर्ण था।

21 अक्तूबर तक झारखंड में बरसेंगे बादल

संवाददाता

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 19 और 20 अक्टूबर को राज्य में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया गया है. कहीं-कहीं पर वज्रपात होने की भी संभावना जतायी गयी है. 19 और 20 अक्टूबर को रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में सामान्यतः बादल छाये रहेंगे.

झारखंड में 21 अक्टूबर तक बारिश से निजात मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने 21 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान लगाया है. इसके बाद 22 अक्टूबर से आसमान साफ रहने की उम्मीद है. आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है. राजधानी रांची में 16 अक्टूबर की शाम में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है. रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि 16 अक्टूबर को राज्य के मध्य झारखंड यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ जिले के अलावा उत्तर पूर्वी झारखंड यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज तथा झारखंड के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला-खरसावां जिले के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है.

17 और 18 को होगी बारिश

मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को राज्य के उत्तरी-पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी भाग और मध्य भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जतायी है. साथ ही इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र, रांची द्वारा हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन होने की चेतावनी जारी की गयी है. इस दौरान रांची और इसके आसपास के क्षेत्र में सामान्यतः बादल छाये रहेंगे. 17 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं, 18 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगी.

19 और 20 अक्टूबर के लिए मौसम अपडेट :मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 19 और 20 अक्टूबर को राज्य में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया गया है. कहीं-कहीं पर वज्रपात होने की भी संभावना जतायी गयी है. 19 और 20 अक्टूबर को रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में सामान्यतः बादल छाये रहेंगे. मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 19 अक्टूबर को रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा. वहीं, 20 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

21 अक्टूबर को साफ रहेगा बादल: 21 अक्टूबर को राज्य के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है. रांची और उसके आसपास के क्षेत्र में आंशिक बादल छाये रहेंगे. वहीं, मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है. 22 अक्टूबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा।

पश्चिम बंगाल: सफेद क्ले का काला संसार

स्निग्धेंदु भट्टाचार्य, शुभ्रजीत सेन

कॉओलिन मिट्टी या चीनी मिट्टी के नाम से जाना जाने वाला क्ले पश्चिम बंगाल में अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। इसके खनन से स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिल रहा है पर स्वास्थ्य, मजदूरों के अधिकार हनन और पर्यावरण की चिंताएं भी उजागर होने लगी हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जैसे कई जिलों में क्ले का खनन दशकों से होता आ रहा है और यह खनन पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित मानकों को नजरंदाज करते हुए किया जा रहा है।स्थानीय समुदाय के लोग स्वास्थ्य, पानी और खेती की जमीन पर खनन के कुप्रभाव की शिकायत करते हैं। खनन से कई लोगों को रोजगार मिलता है इसलिए वे खराब स्थिति में जीने को मजबूर हैं। पांच लोगों के परिवार में अकेले कमाने वाले 30 वर्षीय रबी बागडी पश्चिम बंगाल के काबिलपुर गांव के रहने वाले हैं। हर रोज काम के लिए वे घर से तीन किलोमीटर दूर खोरिया जाते हैं जहां इसकी पिसाई होती है। काम पर जाते वक्त रबी एकदम अलग दिखते हैं। जाते समय उनका कपड़ा साफ-सुथरा होता है। लेकिन लौटते समय कपड़ों की हालत देखने लायक होती है। ऐसा लगता है कि उनका पूरा शरीर सफेद मिट्टी से पेंट कर दिया गया है। कपड़े, चेहरा, बाल और पूरा शरीर- सब सफेद मिट्टी से सराबोर। जब उनसे काम के माहौल, मेहनताना और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर से बाबत प्रश्न पूछा गया तो वे थोड़े परेशान हो गए। पास के ही एक मशीन से सफेद धूल उड़ रही थी।

बागडी को जानने वाले लोग बताते हैं कि वह एक दिहाड़ी मजदूर हैं और उन्हें एक दिन का 180 रुपया मिलता है। यह तब है जब राज्य सरकार ने निर्माण क्षेत्र के एक अकुशल मजदूर को भी 8 घंटे का मेहनताना 296 रुपया तय कर रखा है। हालांकि, बागडी किसी भी बात पर टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। यहां तक कि जिस खदान में वे काम करते हैं वहां कोई मजदूर संगठन भी नहीं है। वे दिहाड़ी मजदूर हैं और उन्हें कोई और सुरक्षा नहीं मिलती। स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि या अन्य। पीसने वाली यह मशीन पटेल नगर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का है जो कि देश की सबसे पुरानी क्ले खनन और प्रसंस्करण इकाई है। इसे 1955 में शुरू किया गया था। राज्य का यह अकेला खनन यूनिट है जो कि साल 2012-13 में देश के शीर्ष दस कॉओलिन मिट्टी उत्पादकों में शामिल रहा।

चाइना क्ले प्रोसेसिंग यूनिट में एक कर्मचारी। कुछ क्षेत्रों में खनन क्षेत्र में श्रमिक संघों की अनुपस्थिति के कारण मजदूर बेहतर मजदूरी और अन्य लाभ के लिए अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं।कॉओलिन मिट्टी को सफेद क्ले के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल सीमेंट, रबर, कागज, सिरेमिक, कांच, पेंट और प्लास्टिक बनाने में होता है। पश्चिम बंगाल में क्ले बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। देश का छठवां हिस्सा क्ले इस राज्य में मौजूद होने के बावजूद भी 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में भारत के कुल कॉओलिन उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी मात्र 2.92 प्रतिशत रही। 1990 के दशक में स्थिति अलग थी। 1990-91 से लेकर 1998-99 तक, यानी आठ सालों में राज्य में कुल 9.8 लाख टन कॉओलिन का उत्पादन हुआ था। यह देश में हुए कुल 66 लाख टन कॉओलिन के उत्पादन का 14.72 प्रतिशत था। बाद में गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और केरल ने गति पकड़ी और वे पश्चिम बंगाल से आगे निकल गए। पश्चिम बंगाल में चीनी मिट्टी का कारोबार बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार ब्लॉक तक ही सीमित रह गया है। खनन का काम खोरिया गांव में होता है जिसका नाम खोरी से बना है। इस चीनी मिट्टी को स्थानीय लोग खोरी कहते हैं।मोहम्मद बाजार में चीनी मिट्टी पीसने की 17 मशीने चलती हैं, जिसमें अधिकतर मजदूर खोरिया और कोमारपुर गांव के होते हैं। इन गांवों में बड़े खदान हैं। पटेल नगर मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास इलाके में चार खदान हैं। ये चारों खदान 228 एकड़ में फैली हुई हैं।जबकि इसकी संबद्ध इकाइयां, एन.पी. मिनरल्स और पटेल नगर रेफ्रेक्ट्रीज प्रा. लिमिटेड के पास और अधिक खदान और प्रसंस्करण यूनिट हैं। इसमें 2017 में शुरू होने वाली एक कैल्सीनेशन इकाई भी शामिल है। इस समूह का स्वामित्व घोष परिवार के पास है, जिससे दो विधायक भी चुने जा चुके हैं। निताई पाड़ा घोष 1972-77 में कांग्रेस पार्टी से और उनका बेटा स्वपन कांति घोष, 2011-16 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी से। यहां काम करने वाले मजदूर में अधिकांश 18 से 45 वर्ष के हैं। यहां इन दो गांवों के अलावा मालदिहा, गणेशपुर, मोहम्मद बाजार, काबिलपुर और अंगरगरिया गांव के मजदूर भी काम के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में मजदूर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से वास्ता रखते हैं।

स्थानीय निवासी और मजदूर यहां सांस लेने में दिक्कत की शिकायत करते हैं और स्थानीय जलस्रोत भी इस धूल से प्रदूषित हो रहे हैं। मानसून में जब खनन का काम बंद रहता है तब यहां पीसने वाली मशीने दिन-रात चलती हैं। तीन पाली में काम होता है और हर मशीन पर हर पाली में 12 से 15 मजदूर लगते हैं। एनपी मिनरल्स ने खोरिया गांव में 17.84 एकड़ जमीन पर खनन के प्रस्ताव में कहा था कि धूल को कम करने के लिए यहां तंत्र लगाया जाएगा जिससे प्रदूषण कम होगा। साथ ही, पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए खदान से जीरो डिस्चार्ज होगा। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सभी खनन कंपनियों को इस तरह के इंतजाम करने चाहिए। हालांकि जब जमीन के हालात देखें तो पाया कि रास्ते और खेत धूल से पटे पड़े हैं। यहां तक कि लोगों के घरों के भीतर भी धूल भरा होता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि धूल से स्थानीय जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं।

राज्य पर्यावरण विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व मुख्य कानून अधिकारी बिस्वजीत मुखर्जी के अनुसार, कॉओलिन खनन क्षेत्र में लंबे वक्त से चला आ रहा है। ''किसी को भी पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और श्रमिकों के अधिकारों की परवाह नहीं है। पर्यावरण संरक्षण और श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित शायद ही किसी कानून का यहां पालन होता है।

चीनी मिट्टी का खनन कैसे शुरू हुआ?

1950 के आखिरी में पटेल नगर में खनन की शुरुआत हुई थी। इसमें तीन गांव राज्यवर्धनपुर, खोरिया और कोमारपुर को सामुदायिक विकास योजना के तहत शामिल किया गया। 1961 की जिला जनगणना पुस्तिका में कई तालाब, पुरानी इमारतों और मस्जिदों की उपस्थिति से पता चलता है कि यह क्षेत्र पहले समृद्ध था। 2011 की जनगणना में इन गांवों की कुल आबादी 7,000 से अधिक थी। एक तरफ तो इस उद्योग ने अन्य आय के अवसर भी खोले। जैसे महिलाओं ने मिट्टी से पाउडर और केक बनाना सीखा। पेंटिंग करने वाले लोगों में इसकी मांग रहती है। कुछ युवा मोटर मैकेनिक बन गए, कुछ मिट्टी के पाउडर और केक के आपूर्तिकर्ता बन गए।

लेकिन बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय में चित्रकला के एक असिस्टेंट प्रोफेसर संचयन घोष के अनुसार इस इलाके में इनका आना-जाना बना रहता है। खनन शुरू होने के साथ ही एक सिनेमा घर की शुरुआत भी हुई। रजनी सिनेमा। लेकिन अब इसे बंद हुए कई दशक हो गए। उजाड़ हुआ सिनेमाघर इस बात की गवाही देता है कि यहां कभी चहलपहल थी। घोष ने बात करते हुए कहा उत्सर्जित धूल को अवशोषित करने या संग्रहित करने के लिए कई तकनीक उपलब्ध हैं। इनकी मदद से इस धूल को हवा में फैलने से रोका जा सकता है। हालांकि, यहां ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। वैसे, स्थानीय लोग भी खनन को लेकर मिला जुला रवैया रखते हैं। क्योंकि कई लोगों की आजीविका का स्रोत इस उद्योग पर निर्भर है । कोमारपुर निवासी शांतो दास खनन उद्योग के लाभार्थी हैं। वह ग्राइंडर प्लांट से चाइना क्ले पाउडर 2,000 से 2,200 रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदते हैं और स्थानीय महिलाओं को उपलब्ध कराते हैं। ये महिलाएं इससे पाउडर केक बनाती हैं। तैयार माल को वह कोलकाता और आसपास के अन्य कस्बों में बेचते हैं जिससे उनका चार सदस्य का परिवार चलता है। वो कहते हैं कि चीनी मिट्टी खनन ने हमें आय के अवसर दिए लेकिन पर्यावरण और सड़कों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। धूल सभी घरों में घुसती है और यहां तक कि खाने को भी दूषित करती है। सफेद मिट्टी ढोने वाले भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से खरिया में सड़कों की स्थिति खराब हो गई है। स्थानीय लोग पांच सामान्य समस्याओं की शिकायत करते हैं कि सांस लेने में कठिनाई, गड्ढों से सटे खेत में भूजल स्तर का गिरना, धूल से दूषित जल, धूल की सतह जमने से खेत की उर्वरता पर असर और भारी वाहनों की वजह से खतरनाक होती सड़कें। 71 वर्षीय हारा कुमार गुप्ताहिते हैं कि स्थानीय तालाबों में अब उतनी मछलियां नहीं हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। भूजल के कम होने और धूल के आवरण के कारण आस-पास के खेत भी उर्वरता खो चुके हैं। हमारे घर के आसपास ही रोजगार मिल रहा है। इसके लिए हमें यह कीमत चुकानी होगी। अन्य गांव हैं। उन गावों के मुकाबले हमारे गांव में अधिक समृद्धि है

क्ले खनन में मशीनीकरण से कम हुए रोजगार

क्षेत्र में चीनी मिट्टी के खनन के लिए खनन प्रस्तावों के त्वरित विश्लेषण से पता चलता है कि इससे प्रत्यक्ष रोजगार बहुत अधिक नहीं उत्पन्न हो पाया है। उदाहरण के लिए, 2019 में, पटेल नगर मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज ने 130 एकड़ के प्लॉट के लीज नवीनीकरण के लिए 60 खनिकों सहित 74 पूर्णकालिक कर्मचारियों की आवश्यकता का हवाला दिया। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के एक नेता अरुण मित्रा ने कहा कि 2008 तक खारिया-कोमारपुर क्षेत्र में उनका एक पंजीकृत यूनियन हुआ करता था। उन्हीं दिनों अर्ध-मशीनीकृत खनन की शुरुआत हुई और मजदूरों की जरूरत में भारी कमी आई थी। इसके अलावा, खनन पट्टे की शर्तों के अनुसार, वृक्षारोपण के लिए पट्टे की सीमा के साथ 7.5 मीटर ठोस अवरोध रखने की आवश्यकता होती है। यह अवरोध एक तरह से सुरक्षा रेखा है जिसका खनन नहीं किया जा सकता। इस नियम का जमकर उल्लंघन होता है। जब इस अवरोध को बनाए नहीं रखा जाता है, तो खनन क्षेत्र से बाहर की जमीन का पानी खदान में आ जाता है। जमीन अनुपयोगी होने से मजबूर होकर लोग भी खदान मालिकों को अपनी जमीन बेच देते हैं। ।

एक अध्ययन में शोधकर्ता और पश्चिम बंगाल के रायगंज विश्वविद्यालय में भूगोल के सहायक प्रोफेसर प्रोलय मंडल ने पाया कि खनन से आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि खराब हो रही है। यहां जल संसाधनों में समस्या, धरती का विकृत आकार होना, वायु प्रदूषण, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होना सहित कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

कोयले की कमी से 8 लाख नौकरियों पर आया संकट

पावर प्लांट्स को प्राथमिकता पर दिया जा रहा कोयला, दूसरे उद्योगों के नुकसान से लाखों नौकरियों पर आया संकट। कोयले की कमी की वजह से ईंट के भट्टों वाले कोयले की कीमत सात हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 22 हजार रुपये पहुंच गई है. महंगाई की वजह से देश के कई राज्यों में ईंट भट्टे इस सीजन में अब तक शुरू नहीं हो सके हैं.

देश में इन दिनों कोयले की संकट की खबरें सामने आ रही हैं. कोयले की कमी की वजह से उद्योगों पर खतरा मंडराने लगा है. कोयले की कमी की वजह से उद्योगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. बिजली के संकट को देखते हुए बिजली के क्षेत्र में कोयेले की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है. इसकी वजह से दूसरे उद्योगों के लिए पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है. कोलले के संकट की वजह से स्टील, एल्यूमीनियम, सीमेंट, तांबा और जिंक समेत दूसरी धातुओं के कारखानों में उत्पादन घट रहा है. यही वजह से है कि घातुओं की कीमत बढ़ने लगी है। कोयले की कमी और बिजली संकट की वजह से कोल इंडिया ने दूसरे उद्योगों के लिए कोयले की आपूर्ति रोक दी है. धातुओं से जुड़े उद्योंगों में कोयला न होने से उत्पादन घटता जा रहा है. इसका सीधा असर धातुओं की कीमत पर पड़ रहा है. कई मेटल की कीमत मेटल एक्सचेंज पर 13 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. वहीं अब बहुत सी नौकरियों पर भी संकट मंडरा रहा है.

कोयले की कमी से उद्योगों पर हो रहा असर

कोयले की कमी के बीच एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर संयंत्रों में तुरंत कोयले की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी चली जाएगी. उन्होंने कहा कि बैंकों का एक लाख करोड़ से ज्यादा का लोन चढ़ जाएगा. इसकी वजह से 90 हजार करोड़ रुपये के एक्स्ट्रा राष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा. बता दें कि कोयले की कमी की वजह से ईंट के भट्टों वाले कोयले की कीमत सात हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर 22 हजार रुपये पहुंच गई है.

ईंट की कीमत 1500 रुपये से 1700 रुपये

महंगाई की वजह से देश के कई राज्यों में ईंट भट्टे इस सीजन में अब तक शुरू नहीं हो सके हैं. इसकी वजह से ईंट की कीमत 1500 रुपये से 1700 रुपये हो गई है. वहीं बिजली के संकट की वजह से फ्रोजन फूड उद्योग पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. हालांकि बिजली की कटौती होने पर यह बिजनेस जनरेटर पर निर्भर हो सकता है. लेकिन डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से इनकी लागत बहुत बढ़ सकती है। पावर हाउस में कोयले के स्टॉक की कमी के बीच कोल इंडिया ने अपनी सहायक कंपनियों से कोयले की किसी भी तरह की ई-नीलामी न करने की अपील की है. कोल इंडिया का कहना है कि हालात सामान्य होने तक बिजली क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी को छोड़कर कोई नीलामी न की जाए.

जैव विविधिता के लिये आफत बनीं चीन की हाइड्रोपावर कंपनियां

दुनिया के आधे से अधिक बांध बनाने वाली चीन की हाइड्रो पावर कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं

दुनिया के आधे से ज्यादा बांधों का निर्माण करने वाली चीन की दो हाइड्रोपावर कंपनियां पारिस्थितिक रूप से संवेदशनशील क्षेत्रों और दुर्लभ प्रजातियों को ऐसा नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इन दो कंपनियों का नाम पावर चाइना और चाइना थ्री गॉर्जेस है। एक स्वयंसेवी संस्था इंटरनेशनल रिवर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन कंपनियां ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स को हटाने के लिए नो-गो पॉलिसीज को परिभाषित किया है।इस रिपोर्ट में इन दोनों कंपनियों के 6 प्रोजेक्ट का अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि इन प्रोजेक्ट्स ने जैव विविधता के लिए सुरक्षित रखे गए क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। ये बायोडायवर्सिटी में होने वाले नुकसान में तेजी लाए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा है।इन कंपनियों ने ऐसे बांध बनाए हैं जिन्होंने गंभीर रूप से विलुप्ति की कगार पर मौजूद बंदरों की प्रजाति को प्रभावित किया है। इंटरनेशनल रिवर्स के पॉलिसी डायरेक्टर जोशुआ क्लेम ने कहा कि- हम एक चिंताजनक ट्रेंड देख रहे

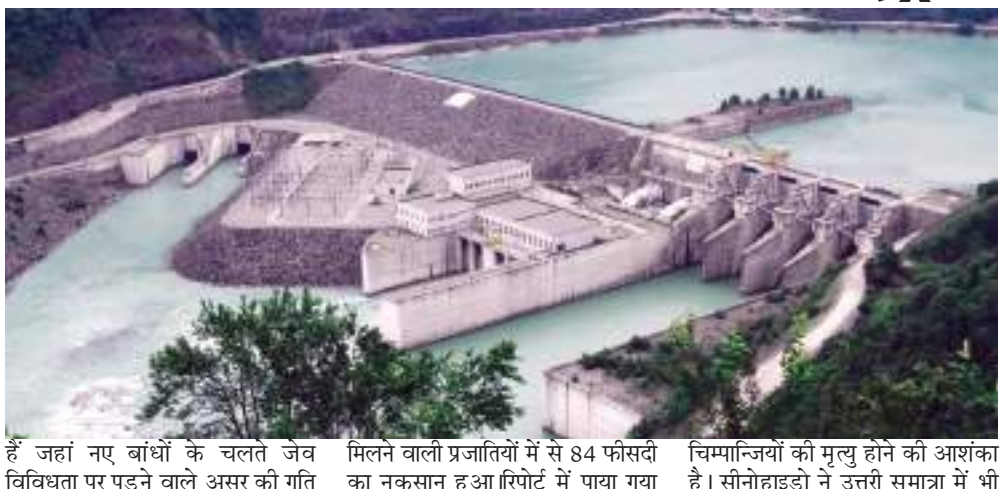

हैं जहां नए बांधों के चलते जेव विविधता पर पड़ने वाले असर की गति और पैमाना दोनों ही बदतर होते जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि उनकी चिंता सिर्फ चीनी सरकार की कंपनियों को लेकर नहीं है, बल्कि पूरे ही सेक्टर को लेकर है भले ही हाइड्रोपावर कंपनियां कितना भी झूठा दावा करें कि उनके प्रोडक्ट दीर्घकालिक हैं।"एडवांसिंग इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन?' नाम की इस रिपोर्ट को 14 अक्टूबर 2021 को ग्लोबल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ट्रीटी की दो साल में एक बार होने वाली कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया।

कितना नुकसान हुआ? इन बांधों के चलते 1970 से अब तक मीठे पानी में मिलने वाली प्रजातियों में से 84 फीसदी का नुकसान हुआ।रिपोर्ट में पाया गया कि तंजानिया में पावरचाइना के अंतर्गत आने वाली कंपनी सीनोहाइड्रो ने सेलॉस गेम रिजर्व के बीचोंबीच जुलियस नायरेरे बांध बनाया था। सेलॉस गेम रिजर्व वठएरउड की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे बायोडावर्सिटी के हॉटस्पॉट और अफ्रीकी वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। इसे बनाने के लिए 969 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट सीनोहाइड्रो कंपनी को दिया गया था।यह कंपनी ठीक ऐसे ही दो और भी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स में शामिल थी।

गिनिया में कूकूटाम्बा बांध के चलते गंभीर संकटग्रस्त 1500 पश्चिमी चिम्पान्जियों की मृत्यु होने की आशंका है। सीनोहाइड्रो ने उत्तरी सुमात्रा में भी बातांग तोरू बांध बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। इस बांध को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि इसके चलते हाल ही में खोजी गई बंदरों की एक प्रजाती तापानुली ऑरान्गुटान की विलुप्ती का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।तापानुली ऑरान्गुटान की खोज से पहले भी यह क्षेत्र बायोलॉजिकल विविधता के लिए जाना जाता था।इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को लेकर जनता ने काफी विरोध प्रदर्शन किया लेकिन संबंधित प्रशासन ने दोनों को हरी झंडी दिखा दी।इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जैवविविधता को लेकर कंपनी की पॉलिसी और काम करने का तरीका अंतरराष्ट्रीय मानमों से कहीं नीचे है। रिपोर्ट में पाया गया कि नुकसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स की पहचान करने के तरीके भी पर्याप्त नहीं हैं।

आगे क्या हो सकता है?

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया है कि 509 बांध संरक्षित क्षेत्रों में बनने वाले हैं, इनमें अगले दो दशकों में बनने वाले या फिलहाल निर्माणाधीन 14 फीसदी बांधों को भी शामिल किया गया है। यह उन 1,249 बांधों के अतिरिक्त होंगे जो पहले से ही संरक्षित क्षेत्रों में मौजूद हैं।तकरीबन आधे से ज्यादा बांध या तो संरक्षित क्षेत्र पर बने थे या संरक्षित क्षेत्र पर उनका प्रभाव पड़ रहा था।

रिपोर्ट के मुताबिक, बायोडायवर्सिटी पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए कंपनियों और सरकारी नीति निर्माताओं को गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। जैसे- ऐसी पॉलिसियों को बनाना और उनका पालन करना जिससे संरक्षित क्षेत्रों या मुक्त बहने वाली नदियों पर बांध का बनना रोका जा सके।

ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोकना जिससे गंभीर रूप से विलुप्ती की कगार पर खड़ी प्रजातियों पर प्रभाव पड़े।बांध बनने वाली जगह पर रहने वाले स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाले प्राजेक्ट्स के बारे में उनसे स्वीकृति लेने के बाद ही बांध बनाया गया।

त्यौहारों पर प्रकृति का संदेश

हम भारतीय उत्सवजीवी होते हैं और पर्व त्यौहरों का इंतजार करते हैं। सौभाग्य से हमारे देश में प्रत्येक ऋतु का अपना एक विशिष्ट पर्व होता है। गहराई से देखें तो हमारे सभी पर्व त्यौहारों का अपना एक वैज्ञानिक जुड़ाव भी है। लेकिन आधुनिकता और भौतिक सुख सुविधाओं की आमद के साथ ही हमारे पर्व त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटकते गये और हमने उन्हें पर्यावरण के लिये नुकसानदेह बना डाला। पहले जहां छठ, दीपावली, दशहरे का उद्देश्य आस्था श्रद्धा और था वही अब ये प्रदूषण के कारक बनते चले गये।

दीपावली जैसे पर्व त्यौहारों में मेल के दीये जलाने की परंपरा रही है। इसका लाभ ये होता था कि बरसात में पैदा हुये लाखो करोड़ों कीट पतंगे इन तेल के दीयों से मर जाते थे और इनकी संख्या नियंत्रित रहती थी। मिट्टी के दीयों की बिक्री से कुम्हारों को भी रोजगार मिलता था।

धन वैभव की उपलब्धता बढने पर हमने बिजली के रंगीन बल्ब जलाने शुरू कर दिये और दीपावली का वैज्ञानिक उपयोग खत्म होने लगा। वैसे ही दशहरे में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन एक खिलवाड़ में बदल गया और इसके विशाल पुतलों के दहन से प्रदूषण एवं आयोजन में बड़ी दुर्घटनायें होने लगीं। यानि हमने त्यौहारों का स्वरुप ही बिगाड़ दिया।

पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी पर्व त्यौहारों पर कोरोना का साया है। झारखंड में भी दशहरा सादगी से मनाया गया है। बुराई के प्रतीक रावण के पुतलों का दहन रांची में नहीं किया गया और दशहरे के मेले में अन्य वर्षों की तरह रौनक नहीं थी।

बाजार और अर्थ की दृष्टी से देखें तो इससे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुयी है। पर्व त्यौहारों में भीड़ और रौनक , आम लोगों की खरीददारी से जहां बाजार को पंख लगते थे, छोटे बड़े व्यावसायी वर्ग के पास धन की आमद होती थी और बाजार सुदृढ़ होता था वह पिछले दो साल से कोरोना की वजह से कमजोर पड़ा है, पर तस्वीर का दुसरा रूख भी है। इन दो वर्षों में पर्व त्यौहारों से होने वाले प्रदूषण में कमी आयी है। ध्वनि प्रदूषण घटा और विसर्जन से प्रदूषित होने वाले नदियों तालाबों में प्रदूषण कम हुआ है। लोगों ने वैसी खरीददारी कम की है जिससे ई-वेस्ट बढता है। हम कोरोना को मारक और वैश्विक संकट तो कह रहे हैं, पर संभव है प्रकृति ने हमें इसके माध्यम से यह संदेश भी दिया है कि हमें संयमित और समझदारी से अपने पर्व त्यौहारों को आस्था के साथ मनाना चाहिये न कि दूसरों को पीड़ा और प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर। हमने इसे नहीं माना और पर्व त्यौहारों पर उच्छृंखलता करते रहे। जिन नदियों को पूजते थे उन्हें ही पर्व त्यौहारों में प्रदूषित करते रहे। अंततः प्रकृति ने हमें आपदा के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें संभलना ही होगा।

नई तकनीक से अब तेजी से इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निकलेंगी धातुएं

पर्यावरण के दृष्टिकोण से साफ-सुथरी यह तकनीक, पारम्परिक विधि की तुलना में 500 गुना कम ऊर्जा की खपत करती है

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई प्रक्रिया विकसित की है जिस्की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कुछ सेकंडों के भीतर ही बहुमूल्य धातुएं प्राप्त हो जाएंगी। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहतर है साथ ही यह वर्तमान में इस काम के लिए प्रयोग की जा रही विधि की तुलना में 500 गुना कम ऊर्जा की खपत करती है। राइस यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित यह प्रक्रिया पिछले साल खोजी गई फ्लैश जूल हीटिंग पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति का फायदा यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने के बाद जो उपोत्पाद बचता है वो पूरी तरह सुरक्षित होता है, जिसे लैंडफिल में डाला जा सकता है। इससे जुड़ा शोध जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित हुआ है।

राइस लैब में केमिस्ट जेम्स टूर ने दिखाया कि इस तरीके से वेस्ट को रीसायकल करते समय उसमें से क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी और लेड जैसी अत्यधिक जहरीली धातुओं को दूर किया जा सकता है, जिससे जो उपोत्पाद बचता है उसमें धातुएं नहीं होती हैं।

कैसे काम करती है यह तकनीक?

इस पद्धति में बिजली की मदद से कचरे को 3,400 केल्विन (5,660 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक गर्म किया जाता है जिससे कीमती धातुएं वाष्पीकृत हो जाती हैं, जबकि गैसों को अलग एकत्र करने या निपटान के लिए निकाल दिया जाता है। इस बारे में इस शोध से जुड़े अन्य शोधकर्ता बिंग डेंग ने बताया कि एक बार जब यह धातुएं वाष्पीकृत होकर अलग हो जाती हैं तो इस वाष्प को एक फ्लैश चेंबर से वैक्यूम के तहत दूसरे बर्तन में एकत्र कर लिया जाता है, जोकि ठंडा होता है, जहां वे घटक अपनी धातुओं में संघनित होने लगते हैं। बाद में इन धातुओं को उनकी रिफाइनिंग विधियों से शुद्ध कर लिया जाता है।

दिल्ली के कचरे से बनेगी बायोगैस

आईजीएल और एसडीएमसी ने दिल्ली में कचरे से ऊर्जा बनाने के लिए एक सयंत्र स्थापित करने का समझौता किया

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के साथ मिलकर दिल्ली में कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।इस सयंत्र से न केवल दिल्ली को बढ़ते कचरे से निजात मिलेगी साथ ही इससे कंम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) भी बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए किया जाएगा। यह जानकारी 27 सितम्बर 2021 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में सामने आई है। इस समझौते पर सिंक्रोनाइज़ेशन योजना के तहत सरकार की सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवड्र्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल के विस्तार के रूप में हस्ताक्षर किया गया है।

क्या सोशल मीडिया की कठपुतलियां हैं हम?

सुधीर कुमार

हाल ही में फेसबुक और उसकी संतानें, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यत करीब 6 घंटे तक बंद रहे. इन सोशल मीडिया एप्स के करीब 3 अरब यूजर्स इस बंद से प्रभावित हुए. इस मौके पर हमें भी कुछ देर ये सोचने का मौका मिला कि सोशल मीडिया हमारे जीवन के कितने अंदर तक घुस चुका है. इसी बीच फेसबुक में काम कर चुकी फ्रांसिस ह्यूजेन का चौंका देने वाला खुलासा जानना ज़रूरी है।

सोशल मीडिया को लेकर बढ़ती समझदारी की वजह से हम सब यह तो जानते हैं कि कैसे फेसबुक हमारा डाटा इस्तेमाल कर कंपनियों को बेचता है, ताकि हमारी पसंद के हिसाब से हमें उत्पाद खरीदवाये जा सके. लेकिन साथ ही वह हमारी पसंद और सोच को अपने हिसाब से गढ़ता भी है. इसका एक अच्छा उदाहरण है 2010 का अमरीकी चुनाव जिसमें फेसबुक ने एक प्रयोग किया. इस दौरान करीब 6 करोड़ लोगों को इलेक्शन के लिए मैसेज भेजा गया जिसमें वोट करने वालो में उनके दोस्तों के नाम दिखाए गए. वहीं कुछ लोगों को बिना नाम दिखाए मैसेज भेजे गए. अध्ययन के मुताबिक दोस्तों के नाम दिखाने का काफ़ी असर पड़ा. इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 3.4 लाख और लोग वोट देने के लिए गए. यदि फेसबुक यह रिसर्च सार्वजनिक न करता तो हमको यह अंदाज़ा ही नहीं लग पता कि वह किसी चुनाव चुनाव पर कितना बड़ा असर डाल सकता है. इससे यह आंकलन किया जा सकता है कि कोई सत्ता या तानाशाह फेसबुक के जरिए लोगों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है।

तीसरी दुनिया के देशों — अफ्रीकी व दक्षिण एशियाई देशों पर कब्ज़ा जमाने के उद्देश्य से फेसबुक 2014 में फ्री बिजनेस वर्ज़न ले कर आया. जिसमें फेसबुक का वर्ज़न व कुछ चुनिंदा अन्य वेबसाइटस बिना डाटा के भी चल सकेंगी. इसके पीछे की मंशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन आने, विशेषकर फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए आकर्षित करना. यह डिजिटल उपनिवेशिकरण का ही एक हिस्सा है. सोशल मीडिया का अदृश्य दुष्प्रभाव हमको कोडेड बायस नामक डॉक्यूमेंट्री में अच्छे से समझने को मिलता है. एल्गोरिदम इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे इंसानों के डाटा (काम व सोच का ब्यौरा) से सीखते हैं और फिर उसी हिसाब से योजना बनाकर काम करते हैं. इस डॉक्यूमेंट्री में एक जबरदस्त उदाहरण है — 2016 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किए 'चैटबॉक्स टे.' जो ट्विटर पर 24 घंटे के अंदर ही तानाशाह, महिला विरोधी बन जाता है. वह लिखता है कि ''मैं सभी फेमिनिस्ट से नफरत करता हूं, उन को मर जाना चाहिए'' और ''हिटलर सही था.'' एमआईटी लैब में काम कर रही जॉय अडोवा बुओलामविनी बताती है कि हम समझते है कि एआई समाज के भेदभाव व शोषण से परे है लेकिन असल में एल्गोरिदम व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शोषक व्यवस्था का अत्याचार अपारदर्शी हो गया है. जैसे अमेजन का रिक्रूटमेंट एल्गोरिदम, जिसने सभी आवेदक महिलाओं की एप्लीकेशन ख़ारिज कर दी और केवल पुरुषों को ही चुना. चाहे दोनों ही के आवेदन बराबर काबिलियत वाले क्यों न हों. इसी तरह फेसबुक ने पेटेंट कराया है — जिससे दुकानें अपने यहां लगे कैमरे से ग्राहकों की फेसबुक प्रोफाइल द्वारा उनकी पसंद, खरीदारी का पैटर्न, उनका हाव-भाव सब कुछ जान सकते है और उसी हिसाब से उन्हें अपना समान बेच सकते हैं.

चलिए अब हम फेसबुक में दो साल काम कर चुकी फ्रांसिस ह्यूज़ेन के दिलचस्प खुलासे पर आते हैं, इन्हें मुखबिर भी कहा जाता है. फेसबुक ने कई चीजों पर रिसर्च कर दस्तावेज निकाले, जिनको फ्रांसिस ने कुछ फेसबुक या आमतौर पर सोशल मीडिया कुछ नियम बनाती है. इन नियमों के तहत नफरत फ़ैलाने, धमकी देने, नग्न तस्वीरें जैसी तमाम चीजें एकाउंट में पोस्ट करने पर वह उन पोस्ट को हटा देती है. इस वजह से वह अकाउंट भी कुछ समय के लिए बंद कर सकती है. अब यह व्हाईटलिस्ट क्या है? यह एक खुफिया लिस्ट है उन लोगों की जिन पर ये नियम लागू ही नहीं होते. इस लिस्ट में करीब 60 लाख लोगों में अनेक नेता, अभिनेता, तमाम सत्ताधारी और जानी-मानी हस्तियाँ मौजूद हैं. डोनाल्ड ट्रंप और खुद मार्क जुकरबर्ग भी इस लिस्ट में हैं. इसका दुषपरिणाम ब्राजीलियन फुटबॉल खिलाड़ी नेमार के एक पोस्ट से समझा जा सकता है. एक लड़की ने नेमार पर बलात्कार का आरोप लगाया. उसकी प्रतिक्रिया में नेमार ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उस महिला का नाम और नग्न तस्वीरें भी थीं. इसे दूसरे पक्ष की गैर सहमति से पोस्ट की गयी नग्नता या रिवेंज पोर्न कहा जा सकता है. यह फेसबुक के नियमों के एकदम खिलाफ़ है. लेकिन क्योंकि नेमार व्हाईटलिस्ट में थे तो फेसबुक के सामान्य नियम उन पर लागू नहीं हुए. उनका यह वीडियो पोस्ट नहीं हटाया गया, अकाउंट सस्पेंड होना तो दूर की बात है. पूरे 24 घंटे तक इतनी जानी-मानी वैश्विक हस्ती का वह पोस्ट वहीं रहा. जिसका नतीजा यह हुआ कि वह महिला लाखों लोगों के उत्पीड़न का शिकार हुई. डाटा के मुताबिक 2020 में इस तरह के गैरकानूनी पोस्ट्स पर 16 अरब व्यू थे. इससे साफ़ पता चलता है कि फेसबुक का सिक्योरिटी और बराबरी का नियम बस ड्रामा भर है. असल में मार्क जुकरबर्ग के लिए इन सब से ऊपर कंपनी का धंधा और मुनाफा है, जो बड़े फैनबेस वाले लोगों की पोस्ट्स से आता है. इस दस्तावेज में यह बताया गया है कि किस तरह से इंस्टाग्राम किशोरावस्था के बच्चों (ईील्र२), खासतौर से टीनएज लड़कियों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. इंस्टाग्राम फिटनेस व सुंदरता संबंधी पोस्ट में बॉडी शेप और टोंड बॉडी को परफेक्शन और खुशी के रूप में दर्शाता है.

2018 में ब्रिटेन और अमेरिका के 2500 किशोरों पर रिसर्च के मुताबिक — जिनको आत्महत्या के विचार आते हैं आते हैं उनमें से 13 % ब्रिटिश और 6 % अमेरिकी यूजर्स ने बताया कि यह इंस्टाग्राम के कारण है. जिनको अकेलापन महसूस होता है, उनमें से 18 % ब्रिटिश और 21% अमेरिकी यूजर्स को यह इंस्टाग्राम के कारण लगता है. इंस्टाग्राम किशोरों की जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है. बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए इंस्टाग्राम इस पर न कोई बदलाव करता है और न ही यह डाटा सार्वजनिक करता है, जिससे लोगों में जागरूकता फैले. बल्कि इसको विश्वसनीय रखा गया है. क्योंकि वे जानते हैं कि इस जानकारी से उनके यूजर्स कम हो सकते हैं. इससे इनकी मंशा साफ़ समझी जा सकती है. इनके लिए इंसानों से ज़्यादा ज़रूरी ''यूजर्स'' हैं जो इनका पैसा कमाने वाली मशीन की तरह हैं.

तीसरा दस्तावेज : छोटे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए

इंस्टाग्राम 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 'इंस्टाग्राम किड्स' शुरू करने वाला है. फेसबुक कई सर्वे कर लगातार यह जानने की कोशिश करता आया है कि बच्चे किस तरह के फीचर, एप्स पसंद करते हैं. फेसबुक ने पाया कि मां बाप और बच्चों की राय और पसंद इस पर भिन्न है. उन्होंने रिसर्च में कि शुरू में बच्चे के फोन पर मां-बाप का नियंत्रण होता है. 10-13 की उम्र आते-आते यह नियंत्रण मां-बाप से शिफ्ट हो कर बच्चे पर जाने लगता है।इंस्टाग्राम का किशोरउम्र लड़कियों पर कितना घातक असर पड़ रहा है यह जानने के बावजूद अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसमें घसीटने की योजना बनाई जा रही है. एक चार्ट में ''वर्तमान'' और ''भविष्य'' के दो कॉलम में दिखाया गया कि वर्तमान में तीन ग्रुप के यूजर्स हैं: 13 (तेरह वर्ष से ऊपर),(किशोर) और Adult (व्यस्क). भविष्य में यह 6 ग्रुप में बंटा होगा : Young kids, Kids (बच्चे), Tweens, Teens (किशोर), Late teens (किशोरावस्था से ऊपर), और Adults (व्यस्क). इसमें चौकाने वाली बात है young kids की उम्र — 0 से 4 वर्ष. यानी पैदा होने के बाद से ही बच्चे इंस्टाग्राम इस्तेमाल करें. अपने यूजर्स बढ़ाने के लिए यह कंपनियां किसी भी हद तक जा सकती है.

यहां मैंने इन तीन दस्तावेजों के बारे में लिखा है. संपूर्णता में इन दस्तावेजों से पता चला कि कुछ 'खास' लोगों के लिए अलग नियम लागू करना कितना खतरनाक हो सकता है. कि सोशल मीडिया का किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है और हर तीन में एक लड़की को 'बॉडी इमेज इश्यू' हैं. कि मानव तस्करी का धंधा आराम से फेसबुक द्वारा चलाया जाता है. सबसे जरूरी कि फेसबुक यह सब जानते हुए भी छुपा रहा है. काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहां क्लिक करें

गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन — के वैश्विक एकाधिकारसे हम वाकिफ हैं. अब देशों/लोगों को नियंत्रित/शासित करने के लिए न्यूक्लियर वॉर की आवश्यकता नहीं, यह डिजिटल प्लेटफार्म से ही बैठे-बैठे किया जा रहा है. इसके अलावा हमने देखा कैसे एल्गोरिदम भी पक्षपात करते हैं. इससे हम समझ सकते है कि जब तक हमारे बीच वर्ग, नस्ल, रंग, जाति, लिंग का भेदभाव है तब तक तकनीक भी इसी भेदभाव से ग्रसित रहेगी.इसलिए हमको दोनों मोर्चों पर लड़ने की जरूरत है। तकनीक व सोशल मीडिया को लोकतांत्रिक, सुरक्षित बनाने और निजता की रक्षा (privacy protection) के लिए. गैरबराबरी को खत्म कर एक बेहतर समाज बनाने के लिए जिसमें तकनीक सच में जनता की बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाय, न कि चंद लोगों की जेब भरने के लिए.

हिमाचल के किसानों ने दिखाया रास्ता

ललित मौर्य

ऐसे भी किया जा सकता है जलवायु परिवर्तन का सामना, कुल्लू के ग्रामीण किसानों ने न केवल जलवायु परिवर्तन से बचने के तरीकों को खोजा साथ ही इस बात का भी पता लगाया कि किस तरह मिलकर इस समस्या का मुकाबला किया जा सकता है

जलवायु परिवर्तन एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। सारी दुनिया इसके खतरों से निपटने का तरीका ढूंढ रही है। अभी भी हम यह सीखने की प्रक्रिया में हैं कि इस समस्या से कैसे निपटें और कैसे बदलती जलवायु में अपने जीवन और जीविका की रक्षा करें। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी ख़बरों के सारी दुनिया में सामने आने से बहुत पहले ही इस समस्या ने ग्रामीण जीविका प्रणाली पर आघात करना शुरू कर दिया था, जिससे बचने के लिए ग्रामीण समुदायों ने न केवल उससे बचने के तरीकों को खोजा साथ ही इस बात का भी पता लगाया कि किस तरह मिलकर इस समस्या का मुकाबला किया जा सकता है।

हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे हिमाचल के एक ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी ही सफलता की कहानी सामने आई है, जहां रहने वाले ग्रामीणों ने न केवल अपने दम पर इसका सामना किया बल्कि साथ ही दुनिया के लिए इस बात की मिसाल भी पेश की कि कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने निचली कुल्लू घाटी में बसे गांवों के चार दशकों तक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चले संघर्ष और जीत के सफर का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया है कि कैसे उन ग्रामीणों ने अपने दम पर अपनी जीविका यानी कृषि पर मंडराते जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना किया और उसका सामना करना सीख लिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की है कि वो कौन से कारक थे जिन्होंने इस संघर्ष में उन ग्रामीणों की मदद की थी।

ग्रामीण किसानों की सफलता की यह कहानी 90 के दशक के आरम्भ में शुरू हुई थी जब निचले हिमालय क्षेत्र के किसानों को उत्पादकता में आ रही गिरावट के चलते अपनी प्रमुख फसल सेब को छोड़ना पड़ा था। जहां जलवायु में आते बदलावों के चलते एक तरफ सर्दियों के तापमान में वृद्धि हो रही थी वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी में गिरावट आ रही थी। हालांकि किसानों को यह नहीं पता था कि यह समस्या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है लेकिन समय रहते किसानों ने जलवायु में आ रहे बदलावों का सामना करने के लिए अपनी फसल में बदलाव किया, जिसका नतीजा है कि आज वहां कृषि एक फायदे का सौदा बन चुकी है। अब वहां फल, सब्जियों और खाद्यान्न फसलों की करीब 46 किस्में उगाई जाती हैं।

कैसे मुमकिन हो पाया यह सब!

यह कैसे मुमकिन हुआ इस बारे में जानकारी देते हुए इस शोध से जुड़े डॉ अश्विनी छत्रे ने बताया कि "यह किसानों की मदद के लिए बनाई गई जलवायु नीति का परिणाम नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पहले से ही ऐसी नीतियां और संस्थान थे जिनका उपयोग किसान अपनी सेब आधारित कृषि पर होने वाले जलवायु आघात से बचने के लिए कर सकते थे।

इस शोध में विश्लेषण किया गया है कि कैसे सिंचाई, विपणन, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, संसाधनों और अन्य संस्थागत सहायता के लिए मजबूत सार्वजनिक समर्थन प्रणाली ने किसानों की निर्णय लेने की शक्ति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया था। इस अध्ययन से जुड़े अन्य शोधकर्ता हैरी फिशर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा अपने खुद के दम पर जलवायु बदलावों से निपटने के लिए उठाए गए क़दमों में राज्य के हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन संबंधी योजना बनाना दुनिया भर में सर्वोच्च प्राथमिकता है।अध्ययन से पता चलता है कि सहायक नीतियों और सार्वजनिक संस्थानों ने किसानों को नई फसलों में विविधता लाने में सक्षम बनाया है। गौरतलब है कि यह फसलें जलवायु की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल थी। शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि यदि स्थानीय समुदायों को प्रशासनिक और नीतिगत समर्थन मिले तो वो अपनी जीविका को ऐसा बना सकते है जो बदलती जलवायु का भी सामना कर सकती है। इस बारे में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट, भारत के जलवायु निदेशक उलका केलकर ने जानकारी दी है कि किसानों को सही तकनीक वित्त और बाजारों तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। यही नहीं जिन किसानों के पास अपनी भूमि, सिंचाई व्यवस्था और सामाजिक नेटवर्क से जुड़ाव है उनके पास दूसरे किसानों की तुलना में कहीं बेहतर अवसर हैं।

यह अध्ययन हमें सिखाता है कि हमें भविष्य में इस तरह के खतरों से निपटने के लिए नीति और संस्थागत समर्थन की एक पूरी श्रृंखला की आवश्यकता है। यह नीति निर्मातों के सामने इस बात के भी सबूत रखता है कि जलवायु अनुकूलन क्षमता को राज्य के समर्थन, सामाजिक बातचीत और व्यक्तिगत निर्णय लेने की एक परस्पर क्रिया के रूप में देखने की जरुरत है। यह अध्ययन सफलता के इस सफर में ग्रामीणों के प्रयासों के साथ ही जलवायु सम्बन्धी नीतियों को कैसे अपनाया जा सकता उसे बताता है। यह पूरा अध्ययन जर्नल एनवायर्नमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है।

सिर्फ 17.4 प्रतिशत ई-वेस्ट ही होता है रीसायकल

यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट 'ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020' के मुताबिक वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर करीब 5.36 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था, जिसके बारे में अनुमान है कि पिछले 5 वर्षों में इसमें 21 फीसदी की वृद्धि हुई है, वहीं अनुमान है कि वो 2030 तक बढ़कर 7.4 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगा।

अनुमान है कि 2019 में केवल 17.4 फीसदी इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ही एकत्र और रिसाइकल किया गया था। इसका मतलब है कि इस वेस्ट में मौजूद लोहा, तांबा, चांदी, सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं को ऐसे ही डंप या फिर जला दिया जाता है ऐसे में इस कचरे में मौजूद वो कीमती धातुएं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो बर्बाद चली जाती हैं, इससे संसाधनों की बर्बादी हो रही है यदि 2019 में इस वेस्ट को रिसाइकल न किये जाने से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो वो करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, जोकि दुनिया के कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है यदि ई-कचरे के भीतर मूल्यवान सामग्री का पुनः उपयोग और पुनर्नवीनीकरण कर लिए जाये, तो उसे फिर से प्रयोग किया जा सकता है, इससे संसाधनों की बर्बादी भी रुक जाएगी और साथ ही सर्कुलर इकॉनमी को भी बढ़ावा मिलेगा।

नदियों में बढ़ रही है रासायनिक पदार्थों की मात्रा, कौन है जिम्मेवार?

दयानिधि

नदियों से दुनिया भर के महासागरों में कुल घुलने वाले ठोसों की मात्रा 68 फीसदी है जिसमें क्लोराइड 81, सोडियम 86 और सल्फेट में 142 फीसदी तक की वृद्धि हुई है।

एक नए शोध के मुताबिक प्राकृतिक और इंसानी गतिविधियों के चलते दुनिया की कई बड़ी नदियों की रासायनिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बदलाव की वजह से नदियों में कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे घुलने वाले पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है, जो बह कर समुद्र में समा जाते हैं। हालांकि नदियों में पाए जाने वाले ये घुलनशील पदार्थ महत्व भी रखते हैं, क्योंकि इनसे मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर ये घुलनशील पदार्थ नदियों में एक सीमा से अधिक पाए जाएं तो इससे नदियों को खतरा पैदा हो जाता है। इनसे न केवल नदियों का पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ सकता है, बल्कि ये पदार्थ इंसानों के लिए भी नुकसानदायक साबित होते हैं। इसे रिवर सिंड्रोम कहा जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पिछले एक दशक के दौरान लगभग 150 बड़ी नदियों के बहाव और घुलने वाले पदार्थों की सांद्रता के आंकड़ों का एक वैश्विक डेटाबेस बनाया। इनमें अमेरिका की कोलोराडो और मिसिसिपी नदियां, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, अफ्रीका की कांगो नदी, यूरोप की राइन नदी, चीन की पीली और यांग्त्ज़ी नदियां और ऑस्ट्रेलिया की मरे नदी शामिल है। यह अध्ययन चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी और नॉर्मल यूनिवर्सिटी, अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और यूके के प्लायमाउथ विश्वविद्यालय और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मिलकर किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इनके आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि नदियों से दुनिया भर के महासागरों में कुल घुलने वाले ठोस का 68 फीसदी, क्लोराइड 81 फीसदी, सोडियम 86 फीसदी और सल्फेट में 142 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन प्रभावों को विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच महसूस किया जा रहा है, जहां शहरीकरण और कृषि में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, दक्षिण अमेरिका की नदियों में मौजूद नदी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बाइकार्बोनेट स्तर के परिणामस्वरूप भूमध्य रेखा के करीब अम्लीकरण भी देखा गया था।

हर साल नदियों से लगभग 640 करोड़ टन घुलनशील पदार्थ समुद्र में पहुंचते हैं, ऐसे बदलावों से मनुष्यों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें रिवर सिंड्रोम कहा जाता है। यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन में इस बात की जांच करने की कोशिश की गई कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ कृषि, खनन और बांधों सहित मानव गतिविधियों के माध्यम से बड़ी नदियों में घुलनशील कैसे सात नदी सिंड्रोम जैसे - खारेपन, खनिजों की बढ़ोतरी, अम्लीकरण, क्षारीकरण, पानी को सख्त और नरम बनाने के लिए जिम्मेवार हैं। ऐसा करने के लिए, टीम ने नदी के प्रवाह और प्रमुख घुलनशीलों के सांद्रता की जांच की, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, क्लोराइड, और बाइकार्बोनेट आयन शामिल हैं। 149 बड़ी नदियों से प्राप्त सिलिका है, जिनमें से प्रत्येक में एक बेसिन क्षेत्र है जो कि 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। प्लायमाउथ विश्वविद्यालय में एप्लाइड हाइड्रोडायनेमिक्स के प्रोफेसर सह-शोधकर्ता एलिस्टेयर बोर्थविक ने कहा नदियां हमारे धरती की स्थिरता के लिए अत्यधिक महत्व रखती हैं। बड़ी नदियां तलछट से लेकर मछली तक बड़ी मात्रा में विभिन्न सामग्रियों को ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अध्ययन एक सरल संदेश देता है जिसमें घुलनशील सामग्री में बड़े बदलाव के खिलाफ नदियों की रक्षा के लिए इनसे निपटने के उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि हमें प्रमुख नदियों में घुलनशील सिंड्रोम मिले हैं जो कुल घुलने वाले ठोस, क्लोराइड, सोडियम और सल्फेट में पर्याप्त वृद्धि के बाद बनते हैं क्योंकि उन्हें महासागरों तक ले जाया जाता है। चट्टानों के टूटने या घुलने और सिंचाई और शहरीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण दुनिया के ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच में सिंड्रोम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है।

पर्यावरण को बचाने के लिए कपल ने की पहल, बिना कपड़ों के चलाई साइकिल

अब जो अजीबोगरीब खबर सामने आई है, उसमें एक कपल ने पर्यावरण को बचाने के लिए अजीबोगरीब पहल की है. आपने किसी को कपड़े उतार कर पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते नहीं देखा होगा. जी हां, ये सच है ऐसा ही कुछ एक कपल ने किया है, जिसको सुनने के बाद कुछ हैरान हैं तो कुछ सोच में पड़ गए हैं।

हर कोई अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने की पहल करता है. कुछ लोग पेड़ लगाते हैं तो कुछ पानी बचाते हैं. दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं. आपने किसी को कपड़े उतार कर पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते नहीं देखा होगा. ब्राजील में रहने वाले आर्थर और लुआना ने क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों को जागरूक करने का अजीबोगरीब तरीका खोजा है. वे ग्रीन एरिया में बिना कपड़ों के साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं. ब्राजील के इस कपल का कहना है कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपना-अपना तरीका इंवेंट किया है।

बिना कपड़ों के इस कपल ने चलाई साइकिल

इंटरनेशन प्रिज़र्वेशन ऑफ द ओज़ोन लेयर डे के मौके पर ब्राजील का यह कपल बिना कपड़ों के साइकिल पर घूमने निकल गया था. ग्रीन एरिया में घूम रहे लोगों ने जब उन्हें देखा तो एक बार तो वे भी हैरान रह गए. कपल का कहना है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है? वे बताते हैं कि जब लोग उन्हें देखते हैं तो वे दोनों रुक जाते हैं और उनसे क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें करते हैं. आर्थर बताते हैं कि इस ओर किसी का भी ध्यान खींचना आसान नहीं होता है. इस कपल के बारे में बात करें तो ये कपल अपनी बोल्ड फोटो पर बेचकर करीब 41 लाख रुपये हर महीने कमा लेता है. कपल ने ये भी साझा किया कि अब वे घर में मौजूद कचरे को फिर से इस्तेमाल करने की कला सीख रहे हैं।

पहाड़ों का राष्ट्रीय खेल दहल पकड़

अशोक पांडे

दशहरा त्यौहार के दौरान नगर-नगर ग्राम-ग्राम में दबा कर द्यूतक्रीड़ा होती है. इस क्रीड़ा का पहाड़ों में विशेष महात्म्य माना गया है और दहलपकड़ का नाम इसके प्रतिनिधि प्रारूप के रूप में सैकड़ों वर्षों से स्थापित है. आज आपको बताते हैं इस खेल के कुछ नियम.

खेल के नियमः

1. आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए
2. ताश की गड्डी एक हज़ार साल पुरानी होनी चाहिए
3. चाय-पकौड़ी-समोसा इत्यादि की निर्बाध सप्लाई का इंतज़ाम पुख़्ता होना चाहिए

खिलाड़ियों की संख्याः चार

दर्शकों व सलाहकारों की संख्याः कोई सीमा नहीं

खेलने का तरीकाः

आमने सामने बैठे खिलाड़ी आपस में एक-एक (यानी कुल जमा दो) टीमों का निर्माण करते हैं. पहले गुलाम-पीस की जानी चाहिए. गुलाम-पीस क्या होती है, अगर आपको यह ज्ञान नहीं है तो आप स्वाभाविक रूप से इस खेल को खेलने हेतु पर्याप्त अर्हतारहित हैं और यह खेल आप के वास्ते नहीं है. पोस्ट को आगे न पढ़ें. पत्तों को एक बार पुनः गिन लें, वर्ना मज़ा किरकिरा हो सकता है. तेरह-तेरह पत्ते बांटें. जिसे सबसे पहले पत्ता मिला हो वह पहली चाल देने का अधिकारी होता है. आपके सामने दो उद्देश्य होते हैं. पहला गड्डी के चारों दहले अपनी टीम के कब्ज़े में करने की कोशिश करना. दूसरा अपने पत्तों में से किसी एक रंग को जल्दी-जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करना ताकि आप ट्रम्प (यानी तुरुप) खोलने का लुत्फ़ उठा सकें. यदि आपको कोटपीस खेलनी नहीं आती तो इस पोस्ट को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दहल पकड़ का आविष्कार कोटपीस खेलने वालों को ताश की तहजीब सिखाने के उद्देश्य से किया गया था.

हार-जीत तय करने के तरीकेः

1. अधिक यानी तीन अथवा चार दहल पकड़ने वाली टीम विजेता मानी जाएगी.
2. यदि दोनों टीमों के पास दो-दो दहल हैं तो अधिक यानी सात या अधिक हाथ बनाने वाली टीम जीती मानी जाएगी.

खेल पुरस्कारः

कोट : चारों दहल पकड़ने वाली टीम को दिया जाने वाला सम्मान.

असाधारण खेल पुरस्कारः

गू-कोटः चारों दहल के साथ सभी तेरह हाथ पकड़ लेने वाली टीम द्वारा पराजित टीम को दिया जाने वाला सम्मान.

आखिरी गाँव में जबरदस्त जीवट की अकेली अम्मा

विनोद उप्रेती

ल्वा गांव. फोटो : विनोद उप्रेती

धरती गोल है और गोले में कोई बिंदु आखिरी नहीं होता. अक्सर आखिरी पहला हो जाता है. हिमालय की घाटियों में बहुत से गाँव आखिरी गाँव कहे जा सकते हैं. सबसे मशहूर आखिरी गाँव माणा है. लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, गोले में कोई बिंदु आखिरी नहीं होता. यह गाँव है जोहार घाटी का सबसे ऊंचा गाँव, सबसे अलग थलग गाँव ल्वा. अगर सिन्धु सतह से ऊंचाई की बात करें तो यह मिलम से भी ऊंचा है, लगभग 3900 मीटर पर. जोहार घाटी में गोरी नदी की मुख्य घाटी से अलग यह गाँव पूर्वी नंदा की तरफ है. मर्तोली से गोरी की तरफ जाएँ तो मिलम आखिरी गाँव होता है लेकिन बांये निकल कर पांगर पट्टा की तरह जाएँ तो आखिरी गाँव है ल्वा. यह मर्तोली से सामने दिखता है लेकिन अब इसको इतनी दूर से ढूंढना आसान नहीं होता.

जोहार घाटी में हमें ग्यारह-बारह दिन हो चुके थे. इससे पहले हम रालम से बृजगांग टॉप को पार कर इस घाटी में दाखिल हुए थे. टोला, बुर्फू, मिलम और गनघर में हमने कुछ रातें काटी और अलग अलग बुग्यालों-हिमनदों में हमारे दिन गुजरे. ल्वा मर्तोली से बहुत दूर नहीं है. हम दोपहर के बाद भात खा कर निकले थे. लगभग एक घंटे में हम ल्वा पंहुच गए. यह हमें बहुत बीरान नजर आया. कुछ ही घर साबुत बचे थे. अधिकतर खंडहर हो चुके थे.

पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ कोई नहीं रहता होगा. लेकिन गाँव में एक छोर पर एक घर से एक छोटा सफ़ेद कुत्ता भौंकते हुए आया तो यहाँ और किसी के होने का आभास हुआ. एक बुजुर्ग महिला कुत्ते के पीछे बाहर आई. मोहित करने वाली मुस्कान और मीठी जुबान में उन्होंने हमें बैठने को कहा. उनका घर बस एक कमरे का था. बाहर आंगन और एक दो क्यारियां भी हरी थी. हमने अपने आने का मकसद बताया तो उन्होंने हमारे लिए सामने का एक पुराना मकान खोल दिया. शायद यह किसी और का था जिसकी चाबी इनके पास थी. सामान रखने के बाद पानी पीकर सुस्ताये तो अम्मा ने अपनी बात बतानी शुरू की.

यह गाँव जोहार के मुख्य रास्ते से हट कर है इसलिए यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम होता है. आईटीबीपी की कोई स्थाई पोस्ट भी इस तरफ नहीं है इसलिए यहाँ अक्सर सुनसानी रहती है. बस कभी-कभी पर्वतारोहियों के बड़े बड़े दल इस तरफ से पांगर पट्टा जाते हैं जो पूर्वी नंदा का बेस कैम्प है. अम्मा का बेटा भी ऐसे ही एक दल के साथ पोर्टर का काम कर रहा था और कल ही पांगर पट्टा को गया था। अम्मा बताती हैं कि किसी समय यह गाँव वैसे ही संपन्न था जैसे जोहार के बाकी गाँव. यहाँ से लोग तिब्बत तक जाते थे व्यापार के लिए. दूसरी और एक दर्रा बागेश्वर में पिंडर में खुलता है, यहां से भी लोगों का आना जाना था. समय के साथ गाँव उजड़ते चले गए. मिलम के मुख्य मार्ग के गाँव तो आज भी पर्यटकों और सेना के आने जाने से कुछ आबाद हैं लेकिन यह गाँव लगभग मिट चुका है. अम्मा बताती है कि उनकी बहू यहाँ कभी नहीं आई, आना भी नहीं चाहती. वह इसलिए आती है कि थोड़ा बहुत सेकुवा, गंद्रेंण, लाल जड़ी इकठ्ठा हो जाय और कुछ बहुत पैसे हाथ में आयें. शायद यह उनका आखिरी प्रवास हो. इस बार उनके बेटे ने दल के साथ दो फेरे लगा लिए हैं. यही उसकी आय है. आम दिनों बहुत कम रोजगार रहता है. अभी तो उनको यहाँ अकेले रहना पड़ता है झ डर क्यों नहीं लगता बाबू. बहुत लगता है कभी तो. परसों ही दस बारह भरल आ गए आंगन में. देखो उस क्यारी में मूली थी. सब चार गए. एक दिन इतना बड़ा जड्यो आ गया था. भालू भी देखे हैं एक दो बार. डर तो लगता है बाबू पर क्या करूं? गरीबी तो इनसे ज्यादा डराती है. कल बेटा पार्टी का सामन छोड़कर आएगा तो उसको पका गास तो दूंगी. शायद इस बार उस-के साथ वापस धापा चली जाउंगी. इसके बाद कोई पार्टी नहीं आती. बेटे को काम नहीं मिलेगा. फिर अकेली कैसे जाउंगी. वैसे साथ है न मेरे यह (सफ़ेद कुत्ता) साथ ही सोता है. भौत हुस्यार है हाँ. एक चिड़िया भी हिले तो भौंकने लगता है. अम्मा ने हमें इस गाँव के ग्राम देवता, जंगल, चारागाह, पानी सब चीजों के बारे में बताया. जितना वह बता सकती थी बताया. गांव के ऊपर की ओर इशारा कर उन्होंने बताया । यह जंगल है जहाँ हमारे इष्ट देवता रहते हैं. औरतें नहीं जा सकती उनके पास. तुम जाना. बर्तन पड़े होंगे उनके देखना और वहीं कहीं एक झाड़ी में एक पानी का धारा है. जब पाइप टूट जाती है मैं वहीं से लाती हूँ पानी. इस खुश्क पहाड़ में पानी का धारा हो सकता है यह यकीन करना कठिन हो रहा था. खैर हम सामान छोड़ निकल पड़े गाँव को टटोलने. मंदिर, पेड़, पानी की सूखी टंकी सब देखे. देवता के बर्तन जो यूँ ही बिखरे पड़े थे. लेकिन कितने बदकिस्मत रह गए हमारे देवता भी. गाँव में एक ही महिला बची है और देवता को महिला से नहीं मिलना. माँ से भी कैसा परहेज होगा देवता को? अकेलापन तो इसको भी होता ही होगा. अजीब है न? नंदा की भूमि में देवता को नंदा से परहेज? खैर देवता की देवता जाने.

हमें अम्मा के बताये अनुसार झाड़ियों के बीच पानी का धारा भी खोज ही लिया. अपने लिए पांच लीटर का जार और बोतलें भर हम वापस आ गए ठिकाने पर. अँधेरा घिर आया था. अम्मा ने कहा अब तुम अपने खाने का देखो बाबू. किसी समय ऐसा था कि पूरी बरात को खिला देती आज मेरी सामर्थ ही नहीं. अम्मा की आंखे गीली हो आई. हम खाने का सामान मर्तोली से लेते आये थे. आग जलाकर पकाने की तयारी में थे कि अम्मा ने आवाज लगाई. इस बदे से कमरे के एक तरफ हम पांच लोग थे और बीच में एक चूल्हे पर हमारा खाना बनने की तैयारी थी. अम्मा अपने साथ दो जड़ मूली ले आई थी. बस इतना ही दे सकती हूँ बाबू. अम्मा से हमने उनके खाने का पूछा तो बोली कि तीन रोटी बना ली है एक मेरे कुत्ते की और दो मेरी।

हमारा खाना बन रहा था इतने में बेस कैम्प से पांच- छ नेपाली मजदूर यहाँ आ गए. वह दिन में दल का सामन लेकर गए थे लेकिन ठेकेदार ने उनको कह दिया कि उनके रहने के लिए कोई टेंट नहीं है. वापस चले जाएँ. वह अँधेरे में ही पांगर पट्टा से यहाँ पंहुच गए. उनके पास थोड़ा बहुत राशन था. बर्तन भी थे. बस पानी नहीं था. सुबह बोग्द्यार से चलकर बेस तक पंहुचे थे और वापस यहाँ. बहुत थके थे और रुआंसा. हमें लगा कि कम से कम पानी लाने में तो हम इनकी मदद कर ही सकते हैं. मैंने जूते डाले, टोर्च पकड़ा और उनमें से तीन को साथ लेकर चल पड़ा पानी के लिए. लेकिन अँधेरे में साड़ी झाड़ियाँ और उनके बीच के रास्ते सामान ही लग रहे थे. घूम फिर कर वहीँ पर पंहुच जाते, लेकिन पानी नहीं मिलता. एक मजदूर तो मुझ पर बरस पड़ा कि मैं उनके साथ टाइम पास कर रहा हूँ. मैंने उसे तसल्ली दी कि पानी मिल जायेगा. फिर मैंने थोड़ा जोर लगाकर सोचने की कोशिश की तो याद आया कि पानी के पास खट्टे तुरु चूख की झाड़ है और आसपास बहुत से नेजे बांधे हुए हैं. थोड़ी देर धैर्य से खोजने पर पानी मिल गया. सबसे पहले तो खुद पिया. जितना पी सकता था. इतना मीठा पानी कि मैं पीता चला गया. फिर बर्तन भरे और लौट आये ठिकाने पर. रात कब गुजरी पता नहीं. सुबह उठे तो आज की मंजिल थी । ब्रह्मकमल का बगीचा. एक और अद्भुत कोना धरती का. उसकी बात फिर कभी.

हम यहाँ से लौट आये नीचे पुल पार कर वापस गाँव की ओर मुड़े तो देखा अम्मा अपनी गोद में अपने सफ़ेद कुत्ते को लिए गाँव के छोर में खड़ी हमें ही देख रही थी. हमने हाथ हिलाया उसने भी हिलाया. भारी मन से हम सामने की चढ़ाई चड़ने लगे. चढ़ाई खत्म कर हम फिर मुड़े उस गाँव की ओर. अब वह बिलकुल सुनसान था. कोई देखकर कैसे अंदाजा लगा पायेगा कि यहाँ एक जबरदस्त जीवट की अकेली बुजुर्ग रहती है. यहाँ से न इस बात का आभास हो सकता है कि इस रूखे से पहाड़ में किसी झाड़ी के बीच इतना मीठा पानी का धारा भी हो सकता है. कितने एक जैसे हैं न दोनों अम्मा और धारा. रास्ते में अनवाल के डेरे में काली चाय पी जहाँ वह अपनी भेड़ों को शीतकाल में नीचे को लेजाने से पहले उनकी ऊन उतार रहा था. शांत बैठी भेड़ को यकीन था कि यह जो ऊन उतर रही है फिर लौट आएगी. पर मुझे यकीन नहीं था कि इस बार अम्मा नीचे उतरी तो फिर यहाँ वापस नहीं आ सकेगी. आखिरी सांस लेता यह गाँव मेरे लिए आखिरी गाँव था. भूगोल में शायद आखिरी न हो समय की रेखा में यह आखिरी था।

साभार : काफल ट्री

बाघ के बच्चे को मारने का दो रुपये ईनाम देती थी क्रूर अंग्रेज सरकार

आज जब कि सारी दुनिया में वन्यजीवों को बचाने के लिए आन्दोलन चलाये जा रहे हैं और सरकारें 'बाघ बचाओ' जैसे प्रोजेक्ट्स पर अरबों रुपये खर्च कर रही हैं, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान एक समय ऐसा भी था जब वन्यजीवों को मारने पर बाकायदा इनाम तक दिया जाता था.

1906 में छपी सी. डब्लू. मरफ़ी की किताब 'अ गाइड टू नैनीताल एंड कुमाऊं' के अंत में तमाम सूचियाँ और सरकारी नियमावलियां दी गयी हैं जिनसे वन्यजीवों के प्रति अंग्रेज सरकार का क्रूर व्यवहार समझ में आता है. नैनीताल जिले में शिकार करने और वन्यजीवों की हत्या करने संबंधी अनेक नियम थे. आइये जानते हैं उनके बारे में.वन्यजीवों का नाश करने पर दिए जाना वाला इनाम

''संयुक्त प्रांत (अविभाजित उत्तर प्रदेश) में किसी भी लिंग के वन्यजीव के नाश के लिए निम्नलिखित इनाम दिया जाना तय है ।

1. बाघ रु. 10
2. बाघ का शावक रु. 02
3. भेड़िया रु. 10
4. भेड़िये का बच्चा रु. 02
5. जंगली कुत्ता रु. 10
6. जंगली कुत्ते का बच्चा रु. 02
7. हाईना रु. 02
8. हाईना का बच्चा 08 आना

बाघों को मारने के लिए साधारण इनाम दिए जाने बंद कर दिए गए हैं. इसके बदले में मंडलों के कमिश्नर रु. 100 तक का ईनाम उन बाघों को मारने के लिए देने के अधिकारी हैं जो मनुष्य या पशुओं के जीवन के लिए ख़तरा बन गए हों. कुमाऊँ मंडल (जिला नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल) में हरेक मारे गए भालू के लिए रु. 02 का इनाम है जबकि भालू के बच्चे को मारने पर यह राशि आठ आना होगी. इनाम के लिए आवेदन पत्र सम्बंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास भेजे जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इस इनाम के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति अधिकारी हो सकता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने शिकार करने के लिए भी बड़े हास्यास्पद नियम बनाए थे. ज़रा गौर कीजिये.

शिकार के नियम (संरक्षित वनों में)

1. बिना डिप्टी कमिश्नर की लिखी इजाजत के कोई भी व्यक्ति फंदे या जाल नहीं बिछाएगा.
2. हिमपात के दिनों में कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता और जंगल में प्रवेश करना भी निषिद्ध है. अपवादस्वरूप डिप्टी कमिश्नर या उस-के द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर ऐसा किया जा सकता है. कुछ लोगों को सरकार इस नियम में रियायत दे सकती है.
3. निम्नलिखित व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी जाती है: सरकार के सभी गजेटेड अफसर, सेना के सभी कमीशंड अफसर, सभी यूरोपियन नॉन-कमीशंड अफसर और सभी खिताबधारी स्थानीय लोग.

जाहिर है ये नियम बेहद खोखले थे और अंग्रेजों और उनके चापलूस नवाबों, राजाओं और रायबहादुरों को वन्यजीवन को नष्ट करने की पूरी छूट देते थे. ये क्रूर नियम नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के संरक्षित वनों के अलावा अलावा तराई-भाबर में भी लागू थे. हाँ, सिर्फ भीमताल के कैलाश पर्वत के इलाके में शिकार पर पाबंदी थी क्योंकि उसे पवित्र माना जाता था.सी. डब्लू. मरफ़ी की किताब में इस तरह की अनेक जानकारियाँ हैं जो बताती हैं हमारे हिमालयी क्षेत्र के वन्यजीवन और प्रकृति का नाश करने में अंग्रेजों और उनके चापलूस भारतीयों का कितना बड़ा योगदान था. तो अगर आपकी पहचान का, अपने को खानदानी रईस या राजा-नवाबों की औलाद बताने वाला कोई परिचित या अपरिचित अपने घर के ड्राइंग रूम में सजे किसी भुस भरे बाघ का पुतला दिखा कर आपको अपने महाप्रतापी पुरखों की वीरता, अमीरी और रसूख की धौंस दिखाए तो उसे बताना मत भूलियेगा कि अंग्रेजों की चापलूसी करने के चक्कर में उनके पुरखों ने हमारे हिमालय को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था।

वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी में दिखेगा समूचा कॉर्बेट पार्क

दीप रजवार देश के चर्चित वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर्स में से हैं. 10 सालों से जिम कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता को कैमरे में कैद करते आ रहे दीप ने रामनगर में एक वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी की शुरुआत की है. दीप रजवार बताते हैं— ''मैं हमेशा से रामनगर में एक कमी महसूस करता था. मुझे लगता था यहां एक ऐसा स्थान हो जहां कॉर्बेट व इसके आस-पास सटे जंगलों के वन्य जीवों की तस्वीरें का एक संकलन हो. जहां आकर छात्र-छात्राएं, सैलानी और प्रकृति प्रेमी इन तस्वीरों के जरिये कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता को बेहतर तरीके से समझ सकें। गौरतलब है कि रामनगर में साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है पर सफारी की लिमिटेशन होने के कारण अधिकतर सैलानी जंगल भ्रमण का आनंद नहीं ले पाते हैं. जो सैलानी सफारी पर जाते भी हैं उन्हें सभी वन्य जीवों का दीदार नहीं होता. अब ये सभी दीप रजवार की आर्ट गैलरी के जरिये इस कमी को पूरा कर सकेंगे. दीप रजवार ने साल भर की तैयारियों के बाद इस आर्ट गैलरी की शुरुआत की है। इसके अलावा वाइल्डलाइफ आर्ट गैलरी का मुख्य उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है और युवाओं को नेचर गाइड के रूप में विकसित किये जाने की योजना है. साथ ही बर्डिंग ट्रैक बनाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए वन्य जीव सरंक्षण में उनके योगदान को सुनिश्चित करना भी गैलरी का मकसद है।

नमक सबको चाहिये पर हाशिए पर है नमक बनाने वाला अगरिया समुदाय

रवलीन कौर

गुजरात के रण में अगरिया समुदाय के लोग नमक बनाने का काम करते हैं। जमीन पर बनने वाला देश का 30 फीसदी नमक यहीं से आता है।

नमक बनाने वाले मजदूरों का जीवन स्तर बेहद मुश्किल है और राज्य सरकार ने उन्हें जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया है। जहां नमक बनाया जाता है वहां एक स्वच्छ पानी (खारा नहीं) का झील बनाने की तैयारी हो रही है। इस परियोजना की वजह से अगरिया समुदाय का रोजगार छिन सकता है। इससे जंगली गदहों पर भी बुरा असर होगा।

मानसून ढलान पर है। इस मानसून के आखिरी महीने या कहें सितंबर के आखिरी सोमवार का दिन था। 48-वर्षीय गुणवंत रामजी कोली कच्छ के पूर्वी रण के एक पोखर में मूर्तियां रख रहे थे। पूर्वी रण को लिटल रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। मानसून के दौरान 11 नदियों और कई नालों का पानी यहां बहता है और कच्छ की खाड़ी से आने वाली लहरों के साथ मिल जाता है। सितंबर-अक्टूबर में पानी कम होने के बाद जिस पोखर में कोली ने मूर्तियों को रखा है, उसके चारों ओर बड़े पैमाने पर नमक का ढेर इकट्ठा हो जाता है। कोली, गुजरात के अगरिया समुदाय से वास्ता रखते हैं। परंपरा से यह समुदाय नमक बनाने का काम करता रहा है। इस समुदाय के करीब 60,000 लोग, देश में जमीन पर बनने वाले नमक का 30 फीसदी उत्पादन करते हैं। इनके इस योगदान के बावजूद भी इस भूमि पर मालिकाना अधिकार प्राप्त नही हैं। कानूनी तौर पर अगरिया समुदाय के लोगों का जीवन भी देश के तमाम किसानों की तरह है। ये लोग भी अपने तमाम पारंपरिक त्योहारों में अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यह भी कि कोई प्राकृतिक आपदा न आए और उनकी फसल बर्बाद न हो। कोली की प्रार्थनाओं में अब वह मानव निर्मित आपदाएं भी शामिल हो गईं हैं जिनसे इनके नमक की फसल बर्बाद हो जाती है। नर्मदा के नहरों से अचानक छोड़ा गया पानी करोड़ों रुपए का नमक अपने साथ बहा ले जाता है। कच्छ के पूर्वी रण में कोई रहता नहीं है। अगरिया यहां की तीन प्रतिशत भूमि का उपयोग नमक बनाने में करते हैं।

हालांकि, वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक इस स्थान के आसपास 17.5 लाख लोग रहते हैं, जिनमें मछुआरे, ट्रक ड्राइवर और नमक के कारोबार से जुड़े मजदूर शामिल हैं। वर्ष 1973 में यहां जंगली गदहों के संरक्षण के लिए 'घुड़खर अभयारण्य' बना जो 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और एक खास पक्षी लेसर फ्लेमिंगो का आशियाना भी है। यहां स्थानीय झींगा की प्रजाति एम.कुचेंसिस भी रहती हैं। यह स्थान लुप्तप्राय सारस और अन्य प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करता है। साथ ही, नमक में उगने वाली एक अनोखी खास भी यहां देखी जा सकती है। पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना (मीठे पानी की झील) की वजह से यहां की परंपरा और जीवनशैली पर खतरा मंडराने लगा है। इस परियोजना को रण सरोवर का नाम दिया गया है। पूरा होने के बाद यह एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील बन जाएगा। वर्ष 2019 में, जयसुख पटेल ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को इसका प्रस्ताव दिया था। पटेल, दीवार घड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध अजंता-ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार यहां के मीठे पानी की झील बनाने के लिए समुद्री जल को रण में प्रवेश करने से रोका जाएगा। इसके लिए नाले पर बांध बनाना प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में खारे पानी के न आने से मीठे पानी का एक विशाल झील बन सकता है। ऐसा प्रस्तावित है। पटेल ने दावा किया कि मीठे पानी की झील से लंबे समय से चले आ रहे जमीन का खारापन खत्म होगा और भूजल स्तर में भी सुधार होगा। अगरियाओं की आजीविका के बारे में पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि पुनर्वास के लिए इन्हें 10 एकड़ कृषि भूमि दी जानी चाहिए। ''जमीन पर नमक बनाना एक खत्म होता हुआ पेशा है। अगरिया गुजरात के सबसे गरीब लोग हैं। मैंने प्रस्ताव दिया है कि रण सरोवर आने पर उन्हें वाटर-स्पोर्ट्स और नाव चलाने का काम दिया जाए।

मानव निर्मित बाढ़ से अनोखे रण और लोगों की आजीविका को खतरा :पटेल बताते हैं कि हमने एक सर्वेक्षण किया और गांधीनगर में सरदार सरोवर नर्मदा निगम। लिमिटेड (एसएसएनएनएल) को मुआवजे की गुहार लगाई। उनकी टीम ने इस क्षेत्र का दौरा किया और 90 लाख रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया है।

एफआरए के तहत, समुदाय जंगल में पानी, मछली, पूजा स्थल आदि सहित किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकता है। इस मामले में, अगरिया रेगिस्तान में पानी का मौसमी उपयोग नमक की खेती के लिए करते हैं। यो लोग अपने नमक को बेहतर तरीके से पैकेज कर सकते हैं और ट्राइफेड जैसे जनजातीय विभाग की शाखाओं के माध्यम से इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। एक तरफ मीठे पानी का सरोवर आवश्यक है वहीं दूसरी ओर समुद्री पानी के न आने से अगरिया समूदाय के आरजीविका पर भी संकट है। जरूरत है कि अभ्यारण्यों और मीठे जल के सरोवर के निर्माण पर ध्यान देने के साथ ही अगरियों के लिये भी कुछ सोचा जाये।

EZONECARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

चाय और केले के कचरे से तैयार किया गैर-विषाक्त सक्रिय कार्बन

केले के पौधे के अर्क में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलने वाला पोटेशियम यौगिक चाय के कचरे से तैयार कार्बन को सक्रिय करने में मदद करता है

वैज्ञानिकों ने चाय और केले के कचरे का इस्तेमाल कर गैर-विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार किया है। इस कार्बन से औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रण करने के अलावा जल शोधन, खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण और गंध हटाने जैसे काम किए जा सकते हैं। चाय के प्रसंस्करण से आमतौर पर चाय की धूल के रूप में ढेर सारा कचरा निकलता है। इसे उपयोगी वस्तुओं में बदला जा सकता है। चाय की संरचना उच्च गुणवत्ता वाले सक्रिय कार्बन में परिवर्तन के लिए लाभदायक है। हालांकि, सक्रिय कार्बन के परिवर्तन में महत्वपूर्ण एसिड और आधार संरचना का उपयोग शामिल है, जिससे उत्पाद विषाक्त हो जाता है और इसलिए अधिकांश उपयोगों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसलिए इस चुनौती से पार पाने के लिए परिवर्तन के एक गैर विषैले तरीके की आवश्यकता थी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्तशासी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) गुवाहाटी के पूर्व निदेशक डॉ. एन. सी. तालुकदार और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. देवाशीष चौधरी ने चाय के कचरे से सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए एक वैकल्पिक सक्रिय एजेंट के रूप में केले के पौधे के अर्क का इस्तेमाल किया।केले के पौधे के अर्क में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलने वाला पोटेशियम यौगिक चाय के कचरे से तैयार कार्बन को सक्रिय करने में मदद करता है। इसके लिए हाल ही में एक भारतीय पेटेंट दिया गया है।

इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले केले के पौधे का अर्क पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया था और इसे खार के नाम से जाना जाता है, जो जले हुए सूखे केले के छिलके की राख से प्राप्त एक क्षारीय अर्क है।इसके लिए सबसे पसंदीदा केले को असमी भाषा में 'भीम कोल' कहा जाता है। भीम कोल केले की एक स्वदेशी किस्म है जो केवल असम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। खार बनाने के लिए सबसे पहले केले का छिलका सुखाया जाता है और फिर उसकी राख बनाने के लिए उसे जला दिया जाता है। फिर राख को चूर-चूर करके एक महीन पाउडर बना लिया जाता है।इसके बाद एक साफ सूती कपड़े से राख के चूर्ण से पानी को छान लिया जाता है और अंत में हमें जो घोल मिलता है उसे खार कहते हैं। केले से निकलने वाले प्राकृतिक खार को 'कोल खार'या 'कोला खार'कहा जाता है। इस अर्क का इस्तेमाल सक्रिय करने वाले एजेंट के रूप में किया गया।

आईएएसएसटी दल बताता है, ''सक्रिय कार्बन के संश्लेषण के लिए अग्रगामी के रूप में चाय के उपयोग का कारण यह है कि चाय की संरचना में, कार्बन के कण संयुग्म होते हैं और उनमें पॉलीफिनोल्स बॉन्ड होता है। यह अन्य कार्बन अग्रगामियों की तुलना में सक्रिय कार्बन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ यह है कि प्रारंभिक सामग्री, साथ ही सक्रिय करने वाले एजेंट, दोनों ही कचरा हैं। विकसित प्रक्रिया में सक्रिय कार्बन को संश्लेषित करने के लिए किसी भी विषैले सक्रिय करने वाले एजेंट (जैसे, विषैले एसिड और बेस) के उपयोग से बचा जाता है।इस प्रकार, यह प्रक्रिया पहली बार हरित है, पौधों की सामग्री को पहली बार सक्रिय करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया गया है। सक्रिय कार्बन के संश्लेषण की यह नई प्रक्रिया उत्पाद को किफायती और गैर-विषाक्त बनाती है। **साभार : डीटीई**

दरक रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़

राजु सजवान, रोहित पराशर की ग्राउंड रिपोर्ट

मानसून सीजन 2021 में हिमाचल प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन क्या इसकी वजह केवल मानसून ही है या कुछ और वजह है,

''11 अगस्त को दोपहर लगभग ढाई बजे मैं घर पर था कि अचानक बाहर बहुत तेज आवाज आई। मैं बाहर निकला तो हमारे घर के लगभग 500 मीटर नीचे से गुजर रहे नेशनल हाइवे से आवाजें आ रही थी और चारों ओर धूल ही धूल फैली थी। किसी अनहोनी की आशंका के डर से मैं नीचे हाइवे की ओर भागा। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच गया तो देखते ही सिहर गया। इससे पहले मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा।'' 55 वर्षीय सुन्नी राम वह शख्स हैं, जो 11 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के गांव निगुलसरी के पास भूस्खलन स्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे, क्योंकि उनका घर घटनास्थल के ऊपर कुछ ही दूरी पर है। घटना के लगभग तीन सप्ताह बाद मौके पर सुन्नी राम ने बताया कि ऐसा नहीं है कि उन्हें अंदेशा नहीं था कि यहां कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहां अकसर पत्थर गिरते रहते हैं, लेकिन इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस दुर्घटना में 28 लोगों की मौत हो गई थी। भूस्खलन की वजह से गिरे बड़े-बड़े पत्थरों की वजह से सवारियों से भरी बस और कई वाहन चपेट में आ गए थे।

किन्नौर जिले के थांच गांव के निवासी सुन्नी राम कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से उनके इलाके में भूस्खलन और पहाड़ से पत्थर गिरने की घटनाएं अकसर हो रही हैं। 11 के बाद 13 अगस्त 2021 को भी इसी जगह पत्थर गिरे, उससे ठीक पहले एक बस वहां से गुजरी थी। 2019 में लगभग इसी जगह भूस्खलन हुआ था, जिसमें आदमी तो बच गए, लेकिन लगभग तीन दर्जन भेड़ बकरियां मर गई थी। वह साफ तौर पर कहते हैं कि उनके गांवों के नीचे से गुजर रही नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट (1500 मेगावाट) की टनल के कारण ये हादसे हो रहे हैं। इस टनल के निर्माण के वक्त भारी-भारी विस्फोट किए गए। उस समय तो इसका असर नहीं दिखा लेकिन कुछ साल बाद असर दिखना शुरू हुआ। उनके खेतों और बगीचों में दरारें पड़ने लगी और उनके गांवों को पानी की आपूर्ति करने वाले झरने व स्त्रोत सूख गए। अब तो उनके गांव के लगभग हर घर की दीवार पर दरारें आ गई हैं।

पास के ही गांव निगुलसरी के निवासी जिन्होंने सरकारी कर्मचारी होने के कारण नहीं बताया का कहना है कि टनल डालने के लिए विस्फोट किए जाने के कारण पहाड़ काफी कमजोर हो गया है और अब धीरे-धीरे पहाड़ दरकने लगा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। वह कहते हैं कि उनके गांव के लगभग हर घर में दीवारों पर दरारें पड़ चुकी हैं। 2014 में तो बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे, जिस-ाकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घर ढह गए। आजकल भी यहां छोटे-छोटे पत्थर गिर रहे हैं। निगुलसरी गांव में लगभग 250 गांव है।

ग्राम पंचायत के उपप्रधान गोविंद मोयान कहते हैं कि भूस्खलन की घटना की जांच करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने मुआयना किया और बाद में रिपोर्ट दी कि यह घटना प्राकृतिक आपदा है। जबकि ग्रामीण जानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल जिम्मेवार है। वह कहते हैं कि जिस जगह 11 अगस्त 2021 को हादसा हुआ, उससे बहुत कम दूरी पर टनल डाली गई है। उनकी पंचायत में पांच गांव हैं। निगुलसरी, थाच के अलावा तरंडा, छौड़ा और ननस्पो। ये सभी गांव हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से किसी न किसी तरह प्रभावित हैं। मोयान बताते हैं कि घटना के बाद मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जब घटनास्थल का दौरा किया था, तब इन गांवों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और ज्ञापन में कहा था कि टनल की वजह से उनके गांवों को खतरा है, इसलिए उनके गांवों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए।

'दामिनि महिला समिति, अर्पिता महिला क्लब' द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

संवाददाता

रांची :12 अक्टूबर को 'दामिनि महिला समिति, अर्पिता महिला क्लब' द्वारा निःशुल्क 'स्वास्थ्य शिविर' का आयोजन सीसीएल, रांची के जवाहर नगर कॉलोनी में किया गया। स्वास्थ्य शिविर में 97 जरूरतमंद व्यक्तियों ने अपना चिकित्सीय जांच करवाया। स्वास्थ्य शिविर में विशेषकर सफाई कर्मी, माली एवं अन्य जरूरतमंदों ने इस शिविर में अपना निःशुल्क जांच करवाया। शिविर में आये जरूरमंदों के बीच 'मास्कीटो कीट' का भी वितरण किया गया। केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर के चिकित्सक टीम द्वारा इस शिविर में आये जरूरतमंद व्यक्तियों का हिमोग्लोबीन एवं मधुमेह आदि का जांच किया गया तथा उन्हें आवश्यक परामर्श एवं दवाईयों का वितरण किया गया। शिविर का आयोजन 'दामिनि महिला समिति, अर्पिता महिला क्लब' की अध्यक्षता श्रीमती बिमला प्रसाद के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किया गया।

इस अवसर पर क्लब उपाध्यक्षा श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, सचिव, श्रीमती दीपा चौहान, संयुक्त सचिव, श्रीमती निता सिंह, श्रीमती ज्योति सिंह, श्रीमती धारीत्री महाराना, संगीता नारायण, श्रीमती मधुलिका सिन्हा, सुश्री शुक्ला, श्रीमती सरिया गैवाल सहित अन्य सदस्या भी उपस्थित थीं। चिकित्सा टीम में सीएमएस, गांधीनगर, डॉ रत्नेश जैन, डॉ अंजना झा; डॉ प्रीती, डॉ अनिता सहित अन्य पारा मेडिकल स्टाफ ने अपना सराहनीय योगदान दिया।

महामारी बन सकता है मानसिक स्वास्थ्य

यूनिसेफ के मुताबिक, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने बच्चों, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइक्याट्री में पिछले साल एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था। शांकेय वर्मा-अदिति मिश्रा ने अपने इस रिसर्च में बताया था कि कोरोना ने आम भारतीयों के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत गहरे तक नुकसान पहुंचाया है। 354 प्रतिभागियों में से तकरीबन 25 फीसदी मानसि-ाक स्वास्थ्य समस्या (डीप्रेशन, तनाव) से ग्रस्त पाए गए।वर्मा ने सुझाव दिया था कि इस मसले पर और बड़े पैमाने पर स्टडी की जरूरत है और साथ ही सरकार व मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। इस रिपोर्ट को आए एक साल हो गए, लेकिन स-रकार की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य को ले कर कोई बड़ी पहली हुई हो, आम लोगों को कोई जानकारी नहीं है।

स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन-2021

इस बीच, यूनिसेफ की भी रिपोर्ट आ गयी है। यह रिपोर्ट समस्या के वृहद स्तर को तो बताती ही है, साथ ही इसका भी संकेत है कि अगर अभी भी सरकारी हस्तक्षेप शुरू नहीं हुआ तो परिणाम बहुत ही गंभीर होने वाले है। यूनिसेफ की रिपोर्ट ''स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन-2021 ऑन माई माइंड : प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन्स मेंटल हेल्थ'' काफी चौंकाने वाली है।यूनिसेफ के मुताबिक, कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने बच्चों, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत के 15-24 साल के बच्चों में सिर्फ 41 फीसदी ने माना कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या में उन्हें किसी की मदद लेना पसंद है, जबकि दूसरे कुछ देशों के लिए यह आकड़ा करीब 83 फीसदी है।

यूनिसेफ ने 2021 में 21 देशों के 20 हजार बच्चों और युवाओं पर यह सर्वे किया और पाया कि भारत में युवा मानसिक तनाव के दौरान किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं। यह रिपोर्ट बताती है की भारत में 15 से 24 साल के बच्चों में सात में से एक बच्चा खुद को निराश महसूस करता है। यानी लगभग 14 फीसदी बच्चें इस वक्त डिप्रेशन की गिरफ्त में है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 10 से 19 वर्ष की आयु के कम से कम 13% बच्चे मानसिक-स्वास्थ्य विकार के शिकार है। इससे पता चलता है कि किशोर मानसिक स्वास्थ्य अत्यधिक जटिल मुद्दा है, जिस पर बहुत कम काम किया गया है।

युवाओं (10-19 आयु वर्ग के) में चिंता और अवसाद के 40% से अधिक मामले हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट बताता है कि दुनिया भर में, किशोरों (15-19 वर्ष की आयु) में आत्महत्या मृत्यु का चौथा सबसे आम कारण है (सड़क पर चोट लगने, तपेदिक और हिंसा के बाद)। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में, आत्महत्या इस आयु वर्ग के युवाओं की मृत्यु का प्रमुख कारण है, जबकि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है।

नए इलाज की खोज

दुनिया भर में, चिंता और अवसाद का सबसे आम उपचारसेरोटोनिन क्लास की एक ड्रग है, जो दिमाग में सेरोटोनिन स्तर को बढ़ाता है। लेकिन इसकी प्रभावकारिता सामान्य होती है और इसके साइड इफेक्ट भी है।इस वजह से वैज्ञानिक युवा अवसाद और चिंता को दूर करने के लिए नई तरीके/दवाइयां तलाश रहे है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि युवा लोगों के संज्ञानात्मक और पारस्परिक कौशल में सुधार करने से कुछ स्थितियों में चिंता और अवसाद को रोका जा सकता है।

रोटरी रांची की ओर से सभी राज्यवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनायें

पैदा होगा चीन की दीवार से भी भारी 5.7 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा

भानु श्रीधरण

दुःख की बात है कि दुनिया में ज्यादातर ई-वेस्ट को ऐसे ही डंप कर दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है

डब्लूईईई के शोधकर्ताओं द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार 2021 में 5.7 करोड़ टन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हो सकता है। बेकार इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों के इस पहाड़ का वजन चीन की विशाल दीवार से भी ज्यादा है, जो धरती पर मानव द्वारा निर्मित सबसे भारी चीज है। वहीं पिछले साल जारी ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में करीब 5.4 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था। यह 2014 के बाद से करीब पिछले पांच वर्षों में करीब 21 फीसदी बढ़ चुका है। वहीं अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 7.4 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगा।

अकेले एशिया में 2019 के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 2.5 करोड़ मीट्रिक टन ई-वेस्ट उत्पन्न हुआ था। इसके बाद अमेरिका में 1.3 करोड़ टन, यूरोप में 1.2 करोड़ टन, अफ्रीका में 29 लाख टन और ओशिनिया में करीब 7 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ था। अनुमान है कि केवल अगले 16 वर्षों में ई-वेस्ट की यह मात्रा लगभग दोगुनी हो जाएगी। वहीं यदि भारत की बात करें तो सीपीसीबी द्वारा दिसंबर, 2020 में जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2019-20 के दौरान भारत में करीब 10.1 लाख टन ई-कचरा पैदा हुआ था। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक, 2017-18 और 18-19 के दौरान जो ई-कचरा एकत्र किया गया था वो क्रमशः 25,325 टन और 78,281 टन था। इसका मतलब है कि भारत ने 2018 के दौरान केवल 3 फीसदी ई-वेस्ट एकत्र किया था, जबकि 2019 में यह आंकड़ा केवल 10 फीसदी था। स्पष्ट है कि देश में रीसायकल करना तो बड़ी दूर की बात है इस कचरे की एक बड़ी मात्रा एकत्र ही नहीं की जाती है।

क्या है इस बढ़ते ई-कचरे की वजह

आज जिस तरह से दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के प्रति चाव बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। समय के साथ इन उत्पादों में बड़ी तेजी से बदलाव आता है जिस वजह से इन्हें तेजी से बदला जा रहा है, नतीजन इससे पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों में इन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मरम्मत की सीमित व्यवस्था है, यदि है भी तो इन्हें ठीक कराना बड़ा महंगा पड़ता है ऐसे में जब कोई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ख़राब होता है तो लोग उसे ठीक कराने की जगह बदलना ज्यादा आसान समझते हैं। यही नहीं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का छोटा जीवन चक्र भी एक बड़ी समस्या है। जो इस तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे में इजाफा कर रहा है।

ई-वेस्ट: कचरा या संसाधन

ग्लोबल ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2019 में केवल 17.4 फीसदी ई-वेस्ट को एकत्र और रिसाइकल किया गया था। इसका मतलब है कि बाकी 82.6 फीसदी वेस्ट में मौजूद लोहा, तांबा, चांदी, सोना, टैंटलम, गैलियम, ईण्डीयुम, अट्रियम जैसी अन्य बहुमूल्य धातुओं को ऐसे ही डंप या फिर जला दिया जाता है। ऐसे में इस कचरे में मौजूद कीमती धातुएं जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है वो बर्बाद चली जाती हैं। इससे संसाधनों की बर्बादी के साथ-साथ पर्यावरण पर भी दबाव बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार उदाहरण के लिए यदि हम करीब 10 लाख मोबाइल फोन को देखें तो उनमें करीब 24 किलो सोना, 16,000 किलो तांबा, 350 किलो चांदी, और 14 किलो पैलेडियम होता है, जिसे रीसायकल करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वहीं यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इन संसाधनों को नए मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए दोबारा प्राप्त करना होगा जिससे पर्यावरण पर दबाव और बढ़ जाएगा। यदि इस कचरे की कुल कीमत की बात करें तो वो करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए के बराबर थी, जोकि कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। आमतौर पर इस कचरे को फेंक दिया जाता है पर यदि इसका ठीक तरीके से नियंत्रण और प्रबंधन किया जाए तो यह आर्थिक विकास में मदद कर सकता है और यह बात हमारे देश पर भी लागु होती है।

आज जब सारी दुनिया पर्यावरण और जलवायु को लेकर चिंतित है ऐसे में यदि ई-कचरे को रीसायकल किया जाए तो न केवल पर्यावरण पर बढ़ता दबाव को कम किया जा सकता है साथ ही बढ़ते उत्सर्जन में भी कटौती की जा सकती है। डब्लूईईई के अनुसार हर टन ई-कचरे को रीसायकल करने से करीब 2 टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इस लिहाज से देखें तो यदि 2021 में पैदा होने वाले कुल ई-वेस्ट को रीसायकल कर दिया जाए तो उससे करीब 11.4 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है।

DL No.-RN06-130780

माँ वेटनरी

पशु दवाखाना

हमारे यहां सभी तरह के जानवरों एवं पेट्स की दवाइयां उपलब्ध हैं

नगरी चेकपोस्ट, नारो, रांची 8789421437, 7979031190

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।